मध्यप्रदेश में
ब्रॉडबैंड और डिजिटल प्रसारण सेवाओं की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट

(डिजिटल डिवाइड पर बनी एक समझ)

विकास संवाद

मध्यप्रदेश में ब्रॉडबैंड और डिजिटल प्रसारण सेवाओं की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट

(डिजिटल डिवाइड पर बनी एक समझ)

संकल्पना, शोध का डिजाइन और विश्लेषण
सचिन जैन, सौमित्र रॉय, राशि अभिलाषी, अरविंद मिश्रा

आंकड़ों का विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन
राशि अभिलाषी, अरविंद मिश्रा, सौमित्र रॉय

गुणात्मक विश्लेषण
नंदिता छिब्बर

आंकड़ों का संकलन और फील्ड वर्क

शिक्षा ठाकुर, तुषार गोहाटे	(पहल जनसहयोग संस्थान, इंदौर)
रघुवीर ठाकुर, रोशनी मंडोर, अंबाराम मुकाती	(संपर्क, झाबुआ)
रामकुमार विद्यार्थी, मंजू, सोनू सोलंकी, लक्ष्मी	(न्यूसिड-बचपन, भोपाल)
रामावतार तिवारी, लखनलाल शर्मा	(समर्थन, पन्ना)
बलवंत रहांगडाले, फूल सिंह केवटिया, राजकुमार गोप	(न्यूसिड-डिंडोरी)

प्रमुख मार्गदर्शक
शालिनी सिंह (द हिंदू), पवन दुग्गल (सायबर कानूनों के विशेषज्ञ), परंजॉय गुहा ठाकुरता (नई मीडिया के विशेषज्ञ), योगेश कुमार (समर्थन), पुनीत गुप्ता (भारती एयरटेल मप्र-छग), रुद्र मिश्रा (आइडिया सेल्यूलर, मप्र-छग), विनोद गुप्ता (बीएसएनएल), ज्ञानेंद्र तिवारी, मोहम्मद ऐहतेशाम, प्रवीण गोखले, राजीव भार्गव, गुरुशरण सचदेव, चंद्रकांत शेतकर, अनिल निंभोरकर, नीलेश देसाई।

विशेष उल्लेख
डॉ. रवीना अग्रवाल

छायाचित्र
गगन नायर, अरविन्द मिश्रा

इनका हमेशा सहयोग मिला
रोली शिवहरे, फरहत नशीं सिद्दिकी, मनोज गुप्ता, कमलेश नामदेव, संतोष वैष्णव, गुंजन मेंदीरत्ता, राकेश दीवान, सोनू मालवीय।

शोधकर्ता समूह के सदस्य
1. पहल जनसहयोग संस्थान, इंदौर
2. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (न्यूसिड), भोपाल और डिंडोरी
3. संपर्क, झाबुआ
4. समर्थन, पन्ना
5. विकास संवाद

मध्यप्रदेश में ब्रॉडबैंड और डिजिटल प्रसारण सेवाओं की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट (डिजिटल डिवाइड पर बनी एक समझ)

विकास संवाद समिति

संक्षेप : वर्तमान अध्ययन मध्यप्रदेश के पांच जिलों के शहरी (बस्तियों) और गांवों में डिजिटल तकनीक तक वंचित समुदाय की पहुंच, उनकी जानकारी का स्तर और इसके उपयोग को समझने का एक प्रयास है। अध्ययन में उन तथ्यों की झलक मिलती है, जो डिजिटल तकनीक तक वंचित समुदाय की पहुंच और इनके उपयोग को प्रभावित करते हैं, साथ ही इसके मौजूदा स्तर के लिए भी जिम्मेदार हों। इस अध्ययन में डिजिटल तकनीक का संदर्भ मोबाइल फोन, डिजिटल टेलीविजन और इंटरनेट तकनीक से है।

प्रस्तुतिकर्ता : विकास संवाद
ई-7/226, धन्वंतरि कॉम्पलेक्स के सामने,
अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल (मध्य प्रदेश), 462016
फोन : 0755-4252789

प्रकाशन वर्ष : 2015

ईमेल/वेबसाइट : vikassamvad@gmail.com / www.mediaforrights.org / www.digitalinequality.org

डिजाइन : अमित सक्सेना

प्रकाशक : श्री श्रद्धा ऑफसेट प्रिंटर्स, भोपाल

सहयोग : फोर्ड फाउंडेशन

विषय सूची

शब्दावली		1
अध्याय – 1	शोध के बारे में	3
अध्याय – 2	शोध का वैचारिक ढांचा और योजनाबद्ध डिजाइन	5
अध्याय – 3	परिणाम	9
चरण – 1	बेसलाइन सर्वेक्षण	9
चरण – 2	सैंपल सर्वेक्षण	15
चरण – 3	लिंग आधारित सर्वेक्षण	31
अध्याय – 4	गुणात्मक विश्लेषण	45

शब्दावली

उत्तरदाता – परिवार का मुखिया, जो वयस्क व्यक्ति और परिवार में फैसले लेने वाला हो। हालांकि, शोध में परिवार के सभी सदस्यों के जवाबों को समग्र रूप से शामिल किया गया है।

शहरी समुदाय – इसका संबंध रिपोर्ट में शहरी शोध क्षेत्र की झोपड़पट्टी में रहने वाले वंचित समुदाय से है।

शहरी परिवार – इसका संदर्भ शहरी शोध क्षेत्र के झोपड़पट्टी में रहने वाले परिवारों से है।

ग्रामीण समुदाय – इसका आशय शोध क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों से है।

ग्रामीण परिवार – शोध क्षेत्र के ग्रामीण हिस्सों में निवासरत परिवार।

प्राथमिकता परिवार – कुछ निर्धारकों के आधार पर शोध क्षेत्र में परिवारों का चयन प्राथमिकता परिवार के रूप में किया गया। प्राथमिकता परिवारों के चयन के आधार इस प्रकार हैं –

- अगर कोई परिवार धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख , जैन, बौद्ध) से हो।
- किसी परिवार में कोई सदस्य शारीरिक या मानसिक रूप से नि:शक्त हो।
- अगर किसी परिवार की मुखिया महिला हो।
- एकल महिला परिवार।
- वृद्ध और निराश्रित परिवार।

सर्वेक्षण में शामिल नहीं हुए परिवार – सर्वेक्षण के दौरान कुछ घरों में परिवार नहीं मिले, जबकि कुछ में रहवासी परिवारों ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। कुछ घरों में पूरा परिवार रोजगार के लिए पलायन कर गया था, इसलिए सर्वेक्षण अवधि में परिवार की ओर से सूचना देने वाला कोई नहीं मिला।

कामकाजी महिला – ऐसी महिला, जो किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि में संलिप्त हो। भले ही इससे उसे कोई मुआवजा, आय, पारिश्रमिक या लाभ प्राप्त हो रहा हो या नहीं।

मोबाइल फोन के उपयोगकर्ता परिवार – ऐसा परिवार, जिसके पास कम से कम एक मोबाइल फोन है।

मोबाइल फोन उपयोगकर्ता – वह व्यक्ति जिसके पास अपना स्वतंत्र मोबाइल फोन हो और उसमें उसके नाम पर सक्रिय सिम कार्ड लगा हो। सिम कार्ड धारक को मोबाइल फोन उपयोगकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया। अमूमन व्यक्ति अपने सिम कार्ड को किसी परिचित के मोबाइल में भरकर संपर्क के लिए इस्तेमाल कर लेता है।

मोबाइल फोन के उपयोग पर खर्च – फोन करने, एसएमएस भेजने, मोबाइल की बैटरी चार्ज करने, वॉलपेपर/गाने/वीडियो आदि के लिए एक विशेष सिम कार्ड/मोबाइल फोन के स्वयं या परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग के एवज में हुआ खर्च।

इंटरनेट उपयोगकर्ता परिवार – परिवार जो कम्प्यूटर से जुड़े डोंगल/मॉडम के जरिए या फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए ब्रॉडबैंड इंटरनेट का उपयोग करता हो।

इंटरनेट उपयोगकर्ता – इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए जरूरी नहीं कि उसके घर पर इंटरनेट कनेक्शन हो। वह कुछ अन्य जगहों, जैसे इंटरनेट कैफे, एमपी ऑनलाइन, सामुदायिक सेवा केन्द्र, स्कूल, कार्यस्थल, मोबाइल फोन, दोस्तों या किसी संबंधी के घर से भी इंटरनेट का उपयोग कर सकता है।

ब्रॉडबैंड – वह डाटा कनेक्शन, जो परस्पर संवादात्मक सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद करे, जिसमें इंटरनेट भी शामिल है और जिसमें उपयोगकर्ता की वर्तमान मौजूदगी की जगह से सेवा प्रदाता तक आंकड़ों के आदान–प्रदान की न्यूतनतम गति 512 केबीपीएस हो।

कोई कनेक्शन नहीं – वह परिवार जिसके पास डिजिटल टेलीविजन का कोई कनेक्शन न हो।

डिजिटल टीवी कनेक्शन – डिजिटल टेलीविजन कनेक्शन के लिए दो तरह के कनेक्शन को देखा गया है। घरों तक डिश एंटीना के जरिए पहुँचने वाला डिजिटल टेलीविजन प्रसारण (डीटीएच) और केबल और डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से पहुंच रहा टेलीविजन प्रसारण। शोध क्षेत्र में दोनों तरह की डिजिटल प्रसारण सुविधाओं को देखा गया।

एनालॉग टीवी कनेक्शन – केबल या दूरदर्शन के पुराने परंपरागत एंटीना के जरिए टेलीविजन तक पहुँच रहा इस तरह का प्रसारण, जो डिजिटल न हो। इसमें ऐसे परिवारों को भी जोड़ा गया है, जिनके पास टेलीविजन तो है, लेकिन एनालॉग/ डिजिटल कोई भी कनेक्शन नहीं है।

सेवाओं के गुणवत्ता मानक (प्रसारण) – जैसा कि डिजिटल केबल टीवी एड्रेसेबल सिस्टम नियमन 2012 और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं (सेवाओं के गुणवत्ता मानक और शिकायत निवारण) (संशोधित) नियमन 2009 के माध्यम से तय किया गया।

अध्याय 1

शोध के बारे में

पृष्ठभूमि

भारत एक ऐसा देश है, जिसे विरासत में अकूत प्राकृतिक संसाधन मिले हैं। हालांकि, प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण ने देश की आबादी में बड़े पैमाने पर सामाजिक–आर्थिक असमानता पैदा की है। आंकड़े बताते हैं कि देश की 22 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करती है[1], जबकि देश की 26 फीसदी आबादी अशिक्षित है। भारत की आबादी के 32.8 प्रतिशत हिस्से को अभी तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है[2]। आज भी देश के कई हिस्से बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवहन और संचार के बुनियादी ढांचे से महरूम हैं। उल्लेखनीय है कि बुनियादी सुविधाओं से वंचित ये क्षेत्र, जहां लोगों के जीवन स्तर में सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है, या तो भौगोलिक रूप से दूर–दराज के अंचल हैं या फिर दुर्गम ग्रामीण आदिवासी इलाके और वे क्षेत्र जहां जन समुदाय हाशिए पर खड़ा है।

पिछले कुछ वर्षों में इस असमानता को खत्म करने की कई कोशिशें की गईं, ताकि सामाजिक–आर्थिक फासले को भरा जा सके। इसी के तहत आरक्षण जैसी नीति लागू की गई, जिससे हाशिए पर खड़े सामाजिक वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रगति को प्राथमिकता मिल सके। इन सबके बावजूद देश में सामाजिक असमानता बरकरार है और इसका प्रभाव देश में लोगों की उत्पादक क्षमता पर पड़ रहा है।

देश में व्याप्त सामाजिक–आर्थिक असमानता का प्रभाव डिजिटल तकनीक के एक समान उपयोग पर भी पड़ा है, क्योंकि सूचना और संचार के डिजिटल स्रोतों का फैलाव एक–समान नहीं है। हाशिए पर खड़े और वंचित समुदायों को सूचना देने में डिजिटल तकनीक बहुत मददगार हो सकती है और इससे देश के विकास में उनका योगदान भी बढ़ेगा। लेकिन, डिजिटल तकनीक की क्षमता का आंकलन करने पर यह सामने आता है कि इस तकनीक तक सभी की एक समान पहुंच बनाने के लिए इससे जुड़े ढांचागत इंतजामों पर प्राथमिकता से अमल किए जाने की जरूरत थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि जिस डिजिटल तकनीक के कारण सामाजिक–आर्थिक असमानता को दूर करने में मदद मिलनी चाहिए थी, ढांचागत इंतजाम के अपर्याप्त होने के कारण उसमें और इजाफा हो गया।

[1] योजना आयोग (2010–11) के आंकड़े तेंडुलकर पद्धति के आधार पर
[2] जनगणना 2011
[3] ज्यों. द्रेज और अमर्त्य सेन (2002): भारत में लोकतांत्रिक व्यवहार और सामाजिक असमानता, जर्नल ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टनडीज, 37(2), 6–37

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और अन्य स्वतंत्र निजी एजेंसियों द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट और प्रसारण सेवाओं तक पहुँच की स्थिति के बारे में विभिन्न स्तरों पर आंकड़े जारी किए जाते हैं। इनसे भी सूचना–संचार के डिजिटल स्रोतों के बारे में वंचित वर्गों की समझ और पैठ में अंतर को महसूस किया जा सकता है। हालांकि, इस स्थिति को समझने के लिए सरकार की ओर से कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। मौजूदा शोध में मध्यप्रदेश के पांच जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत वंचित समुदाय की ब्रॉडबैंड इंटरनेट और डिजिटल प्रसारण सेवाओं तक पहुँच और वर्तमान स्थिति में उसमें आ रहीं रुकावटों को दर्ज किया गया है।

•••

अध्याय 2

शोध का वैचारिक ढांचा और योजनाबद्ध डिजाइन

शोध का मकसद

मध्यप्रदेश में वंचित समुदायों तक ब्रॉडबैंड और डिजिटल प्रसारण सेवाओं तक पहुँच के बारे में शोध, दस्तावेजीकरण और रिपोर्ट का प्रसार करना, ताकि नीति निर्धारकों को वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए इन सेवाओं तक सभी की एक समान और व्यापक पहुँच को सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

1. शोध क्षेत्र में डिजिटल सूचना–संचार के विभिन्न साधनों की मैपिंग।
2. शोध क्षेत्र में ब्रॉडबैंड, डिजिटल प्रसारण सुविधाओं की उपलब्धता और सेवा प्रदाताओं का आंकलन।
3. डिजिटल संचार के विभिन्न साधनों का विश्लेषण।
4. डिजिटल तकनीक पर आधारित सेवाओं, सुविधाओं की गुणवत्ता और किफायत के साथ उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि का आंकलन।
5. सूचना प्राप्ति और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार पर बहस की शुरुआत करना।

शोध की अवधि

शोध की अवधि एक दिसंबर 2012 से 30 नवंबर 2014 तक दो वर्ष की रही है।

संदर्भ अवधि

शोध के लिए आंकड़े इकट्ठे करने के साधन तैयार किए गए थे। इन्हें शोध क्षेत्र में पहले आजमाया गया और फिर शोध अवधि के पहले चार महीने यानी दिसंबर 2012 से मार्च 2013 के बीच इनमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करने के बाद ही इन्हें अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद, आंकड़े जुटाने, उनके सत्यापन और प्रमाणीकरण का काम शुरू हुआ, जो अगले 8 माह यानी अप्रैल 2013 से नवंबर 2013 तक जारी रहा। इस प्रकार शोध में शामिल

परिवारों की प्रारंभिक स्थिति के अनुमान शोध अवधि के पहले साल यानी दिसंबर 2012 से नवंबर 2013 के बीच सामने आए।

शोध क्षेत्र : फैलाव और दायरा

भौगोलिक दायरा : शोध में मध्यप्रदेश के तीन जिलों के ग्रामीण और दो जिलों की शहरी गरीब बस्तियों को शामिल किया गया है। इसमें पन्ना, डिंडोरी और झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जबकि भोपाल और इंदौर जिलों में शहरी वंचित समुदाय की बस्तियों को शोध क्षेत्र में शामिल किया गया है।

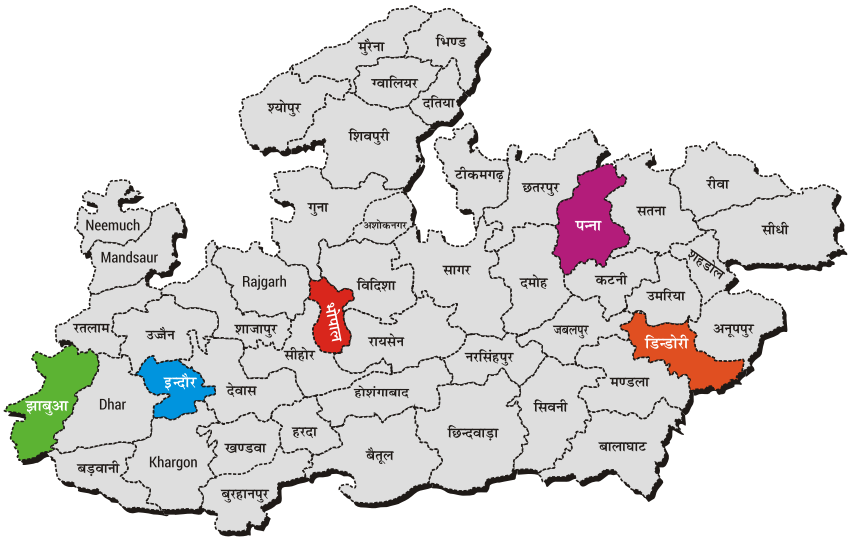

आंकड़े 1 : मध्यप्रदेश के नक्शे में शोध के लिये चुने गये जिलों की स्थिति

सूत्र : http://www.mp.nic.in/images/mp_completed51.gif

सामाजिक क्षेत्र का फैलाव : शोध के लिए उन क्षेत्रों को चुना गया है, जहां वंचित समुदाय की आबादी अपेक्षाकृत अधिक है। शहरी क्षेत्र में झोपड़पट्टियों और ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी बहुल गांवों का चयन शोध के लिए किया गया।

मध्यप्रदेश

शहरी जिले

इंदौर
1. भील पलटन
2. बड़ला
3. राहुल गांधी नगर

भोपाल
1. कृष्णा नगर
2. इंदिरा नगर
3. जाटखेड़ी

ग्रामीण जिले

डिंडोरी (समनापुर ब्लॉक)
1. जाताडोंगरी
2. पोंडी
3. जीलंग
4. सैलाटोला

पन्ना (पन्ना ब्लॉक)
1. माझा
2. कोटा
3. कटरिया
4. शाहपुर

झाबुआ (पेटलावद ब्लॉक)
1. रुपगढ़
2. मातापाड़ा
3. कालीघाटी
4. हनुमंतिया

आंकड़े 2 : शोध क्षेत्र

इस प्रकार शोध में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर कुल 18 यूनिट (6 शहरी बस्तियां और 12 गांव) रहे।

शोध की डिजाइन

शोध को चार हिस्सों में इस प्रकार पूरा किया गया :

1. **समुदाय की प्रोफायलिंग और मैपिंग :** शोध क्षेत्र के दायरे में आने वाले प्रत्येक बस्ती/ गांव के रहवासी समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की गई। ये जानकारियां लक्षित समूह चर्चा (एफजीडी) और गुणवत्तामूलक साक्षात्कार (एप्रीशिएटिव इन्क्वायरी) के जरिए जुटाई गईं। शोध क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारियों को इनके साथ मिलाकर समग्र रूप से समुदाय की प्रोफायलिंग की गई। एफजीडी में निम्न बिंदुओं पर प्रमुख रूप से गौर किया गया :

1. समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति।
2. बुनियादी सुविधाओं तक, जिसमें पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य , शिक्षा, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा भी शामिल है, पहुँच की स्थिति।
3. गांव/बस्ती में ब्रॉडबैंड /इंटरनेट सेवाओं और उनकी गुणवत्ता की स्थिति।
4. गांव/बस्ती में प्रसारण सेवाओं की स्थिति और उनकी गुणवत्ता।
5. मोबाइल फोन सुविधाओं की स्थिति और उनकी गुणवत्ता।
6. इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, मोबाइल और डिजिटल प्रसारण सुविधाओं की ढांचागत उपलब्धता की स्थिति।
7. शोधकर्ता मैदानी टीम ने समुदाय के सहयोग से प्रत्येक गांव/ बस्ती के नक्शे बनाए। समुदाय की बसाहट के बीच उपलब्ध सभी तरह की ढांचागत सुविधाओं को संकेतकों के जरिए नक्शे में दिखाया गया। प्रत्येक गांव/बस्ती के लिए मुख्य रूप से 4 तरह के नक्शे बने। ये इस प्रकार हैं –

1. सामाजिक–आर्थिक नक्शा
2. समुदाय तक मोबाइल फोन की पहुँच का नक्शा
3. समुदाय तक प्रसारण सुविधाओं और टेलीविजन की पहुँच का नक्शा
4. समुदाय तक इंटरनेट की पहुँच का नक्शा

2. **बेसलाइन सर्वेक्षण :** शोध क्षेत्र में समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को समझने और सूचना–संचार के डिजिटल स्रोतों की पहचान के लिए एक बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया।

3. **प्रतिदर्ष सर्वेक्षण :** बेसलाइन सर्वेक्षण में सूचना–संचार साधनों के उपयोग को लेकर सामने आईं समस्याओं की गहराई तक पहुँचने और उपयोग के स्वरूप को समझने के लिए प्रतिदर्ष सर्वेक्षण किया गया।

4. **महिलाओं का सर्वेक्षण :** यह सर्वेक्षण शोध में चुने गए समुदाय की महिलाओं के डिजिटल सूचना–संचार साधनों के उपयोग की जानकारी जुटाने के लिए लक्षित था।

शोध की इकाई

शोध में बेसालाइन और सैंपल सर्वेक्षण के लिए परिवार को इकाई माना गया। महिलाओं के सर्वेक्षण में समुदाय की महिला को व्यक्तिगत इकाई माना गया।

प्रतिदर्ष का आकार

1. **बेसलाइन सर्वेक्षण :** शोध क्षेत्र में 6 बस्तियों और 12 गांवों (कुल 18 ईकाइयों) में 4270 (92 प्रतिशत) परिवारों को बेसलाइन सर्वेक्षण के दायरे में लिया गया। बेसलाइन में शामिल परिवारों का 62 प्रतिशत शहरी और 38 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल था। बेसलाइन में 8 प्रतिशत परिवारों को शामिल नहीं किया जा सका, क्योंकि इन परिवारों के घर या तो खाली मिले या फिर परिवार सर्वेक्षणकर्ताओं को जानकारी देने को तैयार नहीं हुए।

2. **प्रतिदर्ष सर्वेक्षण :** प्रतिदर्ष को दो चरणों में चुना गया। पहले चरण में शोध क्षेत्र के कुल परिवारों के 20 प्रतिशत को प्रतिदर्ष सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग कर शामिल किया गया। दूसरे चरण में बेसलाइन सर्वेक्षण में चिन्हित पांच प्रतिशत प्राथमिक परिवारों को सर्वेक्षण में जोड़ा गया, ताकि प्रतिदर्ष सर्वेक्षण में छूटे वंचित परिवार भी शामिल हो जाएं। इसके पीछे मकसद यही था कि शोध क्षेत्र में रहवासियों के सभी तरह के सामाजिक–आर्थिक चरित्र के परिवारों का समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाए। परिणामस्वरूप प्रतिदर्ष सर्वेक्षण में कुल 1031 परिवार शामिल हुए। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिदर्ष के आकार में शहरी और ग्रामीण परिवारों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व 62:38 ही रहा।

3. **महिलाओं का सर्वेक्षण :** महिलाओं के सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक गांव/बस्ती से 30 महिलाओं को चुना गया। इस तरह शोध क्षेत्र की 18 ईकाइयों में कुल 540 महिलाओं से साक्षात्कार लिए गए। इस तरह 12 गांवों में 360 महिलाएं और 6 शहरी बस्तियों में कुल 180 महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया।

•••

अध्याय 3

परिणाम

चरण : 1 – बेसलाइन सर्वेक्षण

1. उद्देश्य :

(क) समुदाय की सामाजिक–आर्थिक मैपिंग

(ख) प्रत्येद परिवार के स्वामित्व में सूचना–संचार के डिजिटल स्त्रोतों की उपलब्धता।

2. सैंपल की यूनिट :

परिवार

3. सैंपल का आकार :

चुने गए शोध क्षेत्र के 100 फीसदी परिवार (4272 परिवार)

4. शोध के परिणाम

4.1 सामाजिक जननांकीय विश्लेषण

शोध का उद्देश्य यह देखना था कि परिवारों की सूचना–संचार के डिजिटल स्त्रोतों तक पहुँच कितनी है और वे उनका कितना उपयोग करते हैं। इसके लिए सामाजिक वर्ग और जनसंख्या के आधार पर शोध क्षेत्रों की सामाजिक संरचना को जानने की कोशिश की गई।

क. सामाजिक वर्ग : आंकड़े बताते हैं कि हमारे शोध क्षेत्र की सामाजिक संरचना विजातीय है। शहरी क्षेत्रों की सामाजिक संरचना में ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय ज्यादा भिन्नता देखी गई। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के लोग एक ही बस्ती में एक साथ रहते हैं। उनकी जरूरतें समान हैं और संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए एक छोटी सी जगह में लोगों का एक साथ मिल–जुलकर रहना एक संभावित कारण है। लेकिन सामाजिक संरचना में भिन्नता के बावजूद समुदाय के भीतर किसी तरह का बैर नहीं है। वे एक साथ मिल–जुलकर रहते हैं।

शहरी क्षेत्रों में 42% परिवार अनुसूचित जाति के मिले, जबकि अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के

परिवारों का प्रतिशत 25 और 23 है। सामान्य वर्ग के 7% और अल्पसंख्यक वर्ग के 3% परिवार शहरी शोध क्षेत्र के रहवासी हैं।

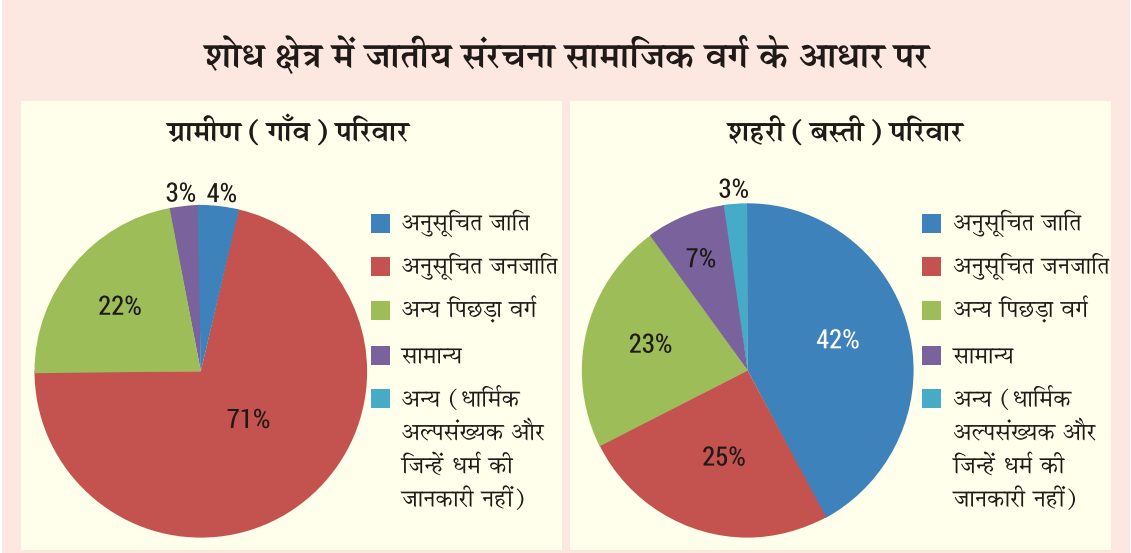

आंकड़े 3: शोध क्षेत्र में सामाजिक वर्गों की स्थिति

ख. जनसंख्या : शोध में कुल 21,768 की जनसंख्या को कवर किया गया। इसमें से 65% शहरी शोध क्षेत्र के और बाकी 35% ग्रामीण शोध क्षेत्र के थे। जनसंख्या की गणना वयस्क महिलाओं, वयस्क पुरुष और बच्चों के आधार पर की गई। शोध के दायरे में आई कुल जनसंख्या के 40% बच्चे, 30% वयस्क पुरुष और 29% वयस्क महिलाएं हैं।

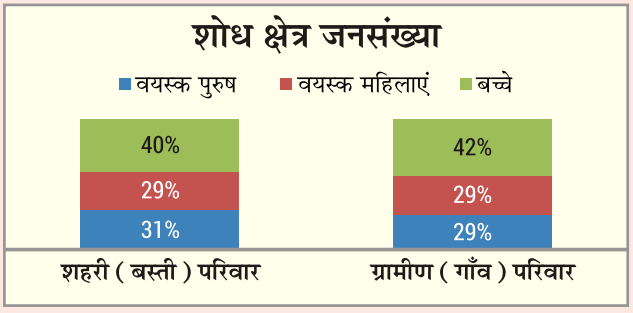

आंकड़े 4 : शोध क्षेत्र का जनसंख्यावार विवरण

4.2 आर्थिक विश्लेषण

सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति को उनकी आजीविका के स्रोत और उनके पास मौजूदा राशन कार्ड के प्रकार के आधार पर आंकलन किया गया है।

क. आजीविका का स्रोत : ज्यादातर परिवार की आजीविका का स्रोत शहरी क्षेत्रों में निर्माण मजदूरी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आजीविका के एक से ज्यादा स्रोतों पर निर्भर हैं। कृषि मजदूरी, खदानों में मजदूरी और मनरेगा के काम में मजदूरी ग्रामीण परिवारों की आजीविका के तीन मुख्य स्रोत हैं।

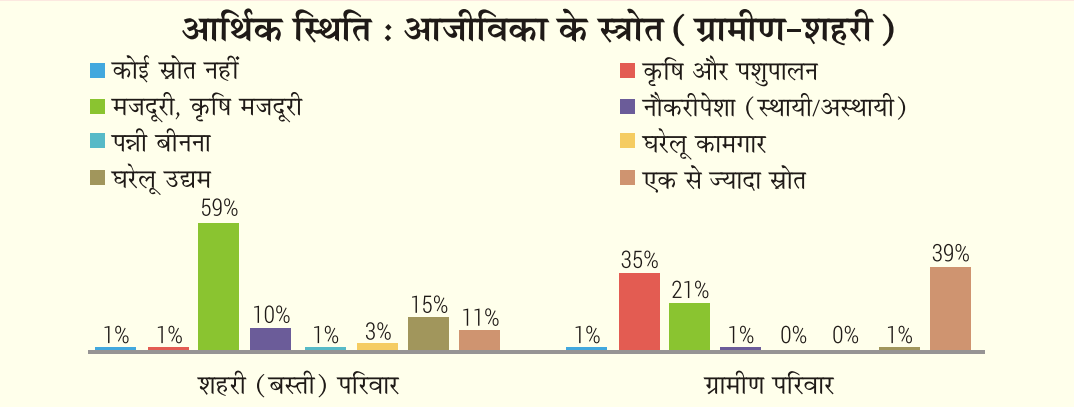

आंकड़े 5 : समुदाय में आजीविका के स्रोतों की स्थिति

ख. राशन कार्ड धारक : सरकार की तरफ से रियायती दर पर राशन लेने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। शोध क्षेत्र के कुल परिवारों में से 30% के पास राशन कार्ड नहीं मिले। वहीं 61% के पास बीपीएल और 15% परिवारों के पास अंत्योदय राशन कार्ड मिले।

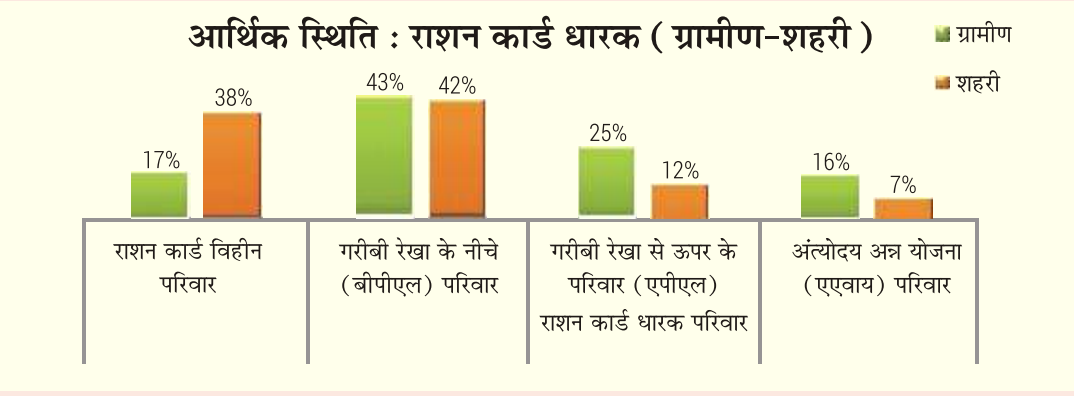

आंकड़े 6 : समुदाय में राशनकार्ड धारकों की स्थिति

4.3 सूचना-संचार के डिजिटल स्त्रोत

आज के समय में वही सशक्त माना जाता है, जिसके पास सूचनाएं उपलब्ध हों। हम जानते हैं कि सूचना प्राप्त करने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में डिजिटल माध्यमों की बड़ी भूमिका है। इसलिए शोध क्षेत्रों में इन माध्यमों की उपलब्धता का आंकलन किया गया। हमने मोबाइल फोन, टेलीविजन और इंटरनेट के रूप में सूचना-संचार के तीन अहम साधनों के बारे में पड़ताल की। कुल परिवारों में से 80% ने इन तीनों में से किसी एक साधन का स्त्रोत के रूप में उपयोग किया है। ग्रामीण परिवारों में यह 57% और शहरी परिवारों में यह 93% है।

क. मोबाइल फोन : मोबाइल फोन सूचना–संचार का सबसे प्रचलित माध्यम है, जिसके सहारे लोग सूचनाओं का आदान–प्रदान करते हैं। शोध क्षेत्र के कुल परिवारों में 72% के पास एक मोबाइल फोन मिला, जबकि 30 प्रतिशत परिवारों के पास एक से अधिक मोबाइल पाए गए। शहरी क्षेत्र में 82% और ग्रामीण क्षेत्र में 56% परिवारों के पास मोबाइल फोन मिले। शहरी क्षेत्र में 53% परिवारों के पास एक मोबाइल फोन मिला, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 47% परिवारों के पास एकमात्र मोबाइल फोन पाया गया।

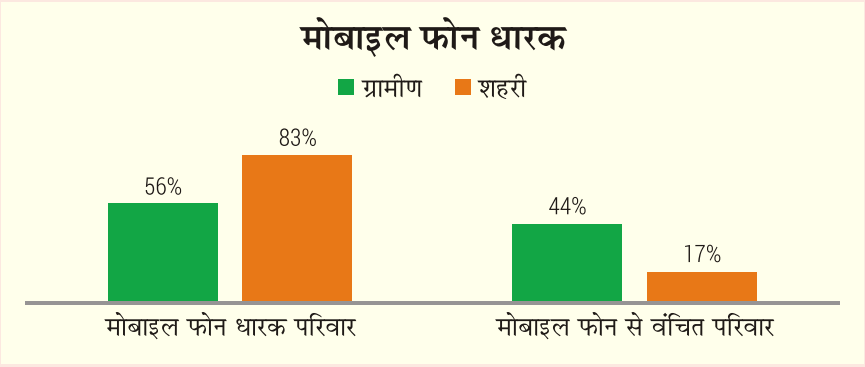

आंकड़े 7 : शोध क्षेत्र में मोबाइल फोन रखने वाले की स्थिति

ख. प्रसारण– टेलीविजन और केबल सेवा : टेलीविजन मनोरंजन के साथ ही सूचना प्राप्ति का एक अहम साधन है। शोध क्षेत्र में 60% परिवारों के पास टेलीविजन पाया गया। शहरी शोध क्षेत्र में टीवी की पैठ ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले ज्यादा मिली। शोध में यह भी देखा गया कि परिवारों के पास सूचना और मनोरंजन के लिए डिजिटल साधन यानी केबल या डीटीएच जैसे कनेक्शन हैं कि नहीं।

टेलीविजन रखने वाले कुल परिवारों में से 50% के पास डिजिटल कनेक्शन (केबल और डीटीएच) और 50% परिवारों के पास परंपरागत एनालॉग कनेक्शन (डीडी 1 का एंटीना) पाया गया, यानी ये डिजिटल टेलीविजन प्रसारण सेवा के दायरे से बाहर पाए गए।

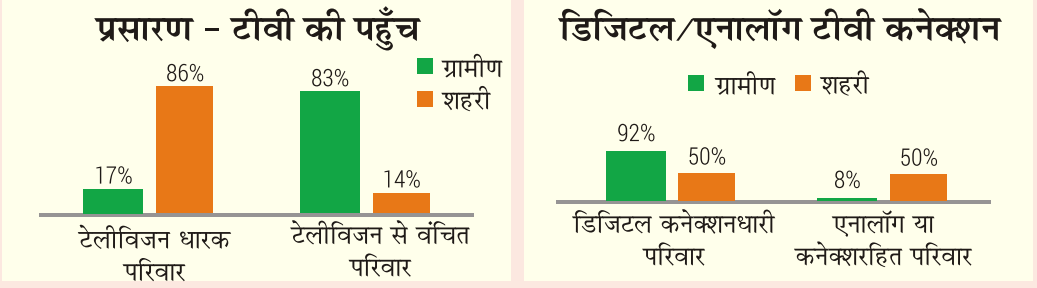

आंकड़े 8 : टेलीविजन प्रसारण सेवा की पहुँच (ग्रामीण–शहरी)

ग. ब्रॉडबैंड इंटरनेट : शोध क्षेत्र में सूचना–संचार के तीसरे स्त्रोत के रूप में इंटरनेट की उपलब्धता का आंकलन किया गया। इंटरनेट मॉडम आधारित और बेतार यानी वायरलैस कनेक्शन के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। शोध क्षेत्र में करीब 52% परिवारों के पास घर पर या तो मोबाइल फोन आधारित, यानी वायरलैस या फिर डोंगल और मॉडम वाले या दोनों तरह के कनेक्शन मिले।

इंटरनेट की पहुँच (शहरी–ग्रामीण)				
	प्रकार ए केवल मोबाइल फोन पर इंटरनेट	प्रकार बी डोंगल/मॉडम पर इंटरनेट	प्रकार सी (ए और बी)	कुल
ग्रामीण परिवार (1617)	49 (3%)	0 (0%)	1 (0.1%)	50 (3.1%)
शहरी परिवार (2653)	163 (7%)	6 (0.3%)	7 (0.3%)	176 (7.7%)
कुल परिवार (4270)	212 (5%)	6 (0.1%)	8 (0.2%)	226 (5.3%)

तालिका–1 : इंटरनेट की पहुँच

LAVA

चरण : 2 – सैंपल सर्वेक्षण

1. उद्देश्य

शोध क्षेत्र के निवासी हाशिए पर खड़े समुदाय में मोबाइल, टेलीविजन और इंटरनेट की पहुँच और इन साधनों के उपयोग को जानना।

2. सैंपल की इकाई

परिवार

3. सैंपल का आकार

शोध क्षेत्र में 1037 परिवारों को सैंपल के लिए चुना गया। इनमें से 636 शहरी और 395 ग्रामीण क्षेत्रों के थे।

4. सैंपलिंग की प्रणाली

पांच जिलों में शहरी और ग्रामीण समुदाय की कुल 18 ईकाइयों में न्यूनतम 20% को सैंपलिंग[4] तकनीक के जरिए चुना गया।

5. शोध के नतीजे

5.1 मोबाइल फोन से संचार : कुल 1031 के सैंपल में 73% के पास मोबाइल फोन मिले। शहरी क्षेत्रों में मोबाइल फोन की पहुंच ज्यादा, यानी 85% परिवारों में जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 53% परिवारों के पास मोबाइल फोन मिले।

5.1.1 मोबाइल फोन का उपयोग और सामाजिक कारक

क. सामाजिक वर्ग और मोबाइल फोन का उपयोग : शोध क्षेत्र के रहवासियों के विभिन्न सामाजिक वर्गों में मोबाइल फोन के उपयोग का अध्ययन करने पर पता चला कि सामान्य वर्ग के 93% परिवारों के पास मोबाइल फोन हैं। इसके मुकाबले अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में मोबाइल फोन की मौजूदगी कम मिली।

[4] विशेष/प्राथमिकता परिवार– ये परिवार अल्पसंख्यक समूह, या फिर ऐसे परिवार जिसमें कोई सदस्य नि:शक्त हो, महिला मुखिया वाला या वृद्ध अथवा परित्यक्त व्यक्तियों वाले परिवार के रूप में देखा गया है।

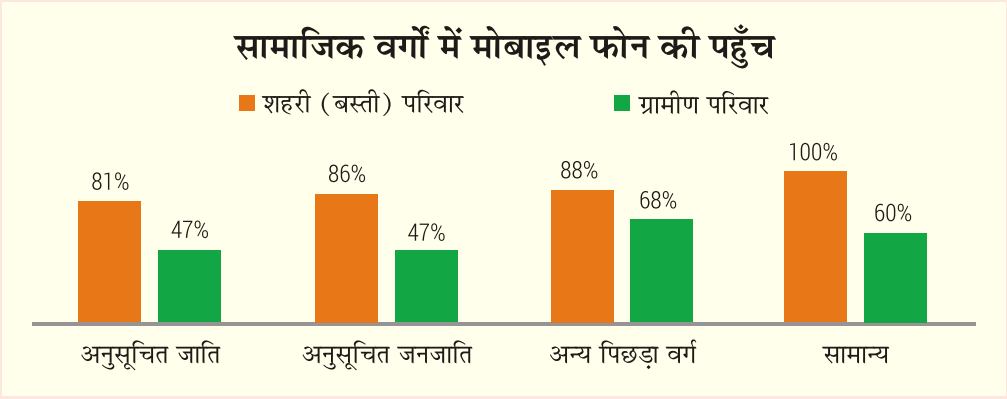

आंकड़े 9 : मोबाइल फोन की पहुँच और सामाजिक वर्ग

ख. आयु वर्ग और मोबाइल फोन का उपयोग : शोध क्षेत्र में 753 परिवारों के पास मोबाइल फोन के उपयोग कर्ता पाए गए। कुल 1093 मोबाइल फोन उपयोकर्ताओं में से 74% शहरी और 26% ग्रामीण क्षेत्रों के थे। इन उपयोगकर्ताओं को उनके आयु समूह के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। इसमें आधे से अधिक (64%) लोग 18–36 साल के आयु समूह के निकले। हालांकि, 18 साल से कम और 50 साल से अधिक के आयु वर्ग में मोबाइल फोन का उपयोग कम दिखाई पड़ा। करीब 7% उपयोगकर्ता 18 साल से कम उम्र के और 6% उपयोगकर्ता 50 साल से ज्यादा उम्र के मिले।

	18 साल से कम	18–36 साल	36–50 साल	50 साल से अधिक	कुल
कुल मोबाइल उपयोगकर्ता	75	702	249	67	1093
प्रतिशत	7%	64%	23%	6%	100%

तालिका–2 : आयु समूह और मोबाइल उपयोगकर्ता

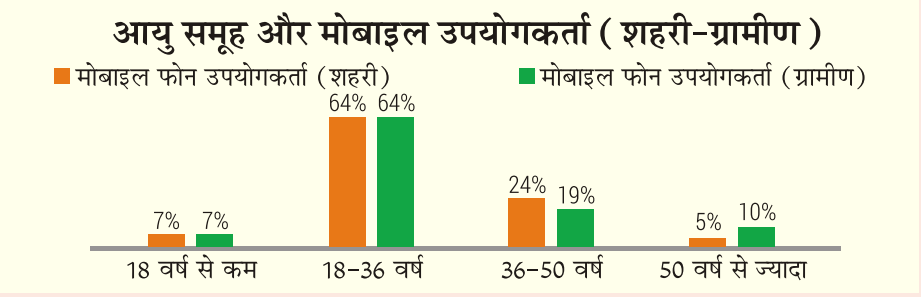

आंकड़े 10 : आयु समूह और मोबाइल फोन

ग. जेंडर और मोबाइल फोन का उपयोग : शोध में पाया गया कि सूचना–संचार का एक उपयोगी और अहम माध्यम होने के बावजूद मोबाइल तकनीक का फायदा लैंगिक वर्ग में एक समान रूप से उपलब्ध नहीं हो रहा है। महिलाओं के द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग को तकरीबन सभी समुदायों में सकारात्मक रूप से नहीं देखा गया।

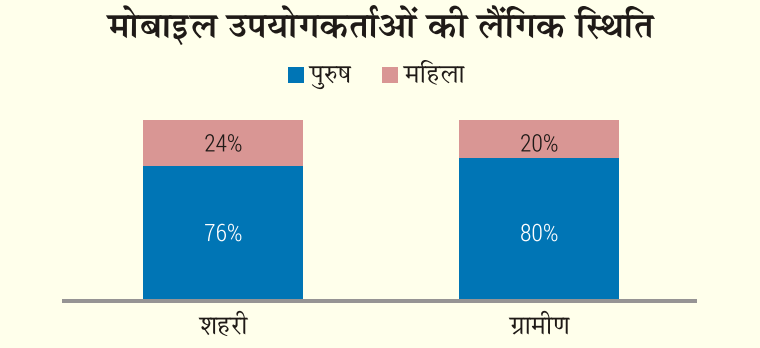

आंकड़े 11 : मोबाइल उपयोगकर्ताओं की लैंगिक स्थिति

5.1.2 मोबाइल उपयोग और आर्थिक कारक

क. आय वर्ग और मोबाइल फोन : शोध में परिवारों को उनकी प्रतिमाह आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। इन वर्गों में मोबाइल फोन के उपयोग का आंकलन किया गया। उच्च आय वर्ग में मोबाइल फोन का उपयोग अधिक पाया गया, जबकि निम्न आय वर्ग में मोबाइल उपयोग कम दिखाई पड़ा। इससे संकेत मिलता है कि परिवार में मोबाइल फोन का उपयोग कितना हो, यह परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।

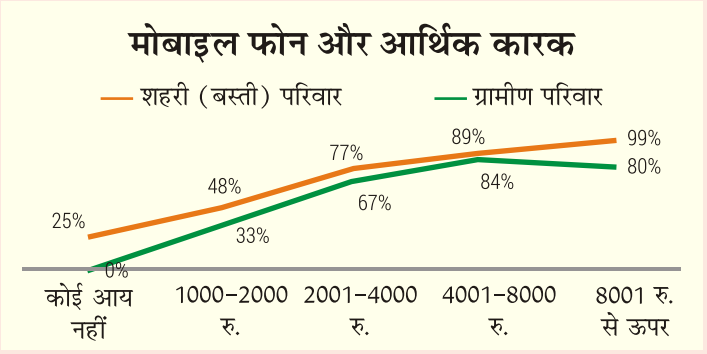

आंकड़े 12 : मोबाइल फोन की पहुँच और आमदनी के बीच संबंध

ख. प्रति उपयोगकर्ता औसत खर्च : मोबाइल संचार पर खर्च – मोबाइल फोन रखने वाले 753 परिवारों के प्रतिमाह खर्च का आंकलन इस शोध में किया गया। हालांकि, उत्तरदाता ठीक-ठीक खर्च नहीं बता सके, इसलिए उनके द्वारा अनुमानित खर्च को दर्ज किया गया। इन परिवारों में से 3% मोबाइल फोन पर प्रतिमाह किए जा रहे खर्च

मोबाइल फोन के उपयोग का खर्च			
	शहर	ग्रामीण	कुल
कुल खर्च (रुपये)	155272	41710	196982
मोबाइल उपयोगकर्ता	807	286	1093
औसत खर्च (रुपये)	192	146	180

तालिका 3 : मोबाइल फोन का मासिक खर्च

को नहीं बता सके। मोबाइल धारक परिवारों का प्रतिमाह औसत खर्च 180 रुपए आया। शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार, प्रति माह औसत खर्च 192 रुपए आया, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के 142 रुपए प्रति माह प्रति परिवार के औसत से अधिक है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की जून 2014 की रिपोर्ट में प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व 119 रुपए है।

मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करने पर प्रतिमाह खर्च : बेसलाइन सर्वेक्षण और समुदाय से चर्चा के दौरान सामने आया कि 5 गांवों में बिजली नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भी कुछ परिवार बिना बिजली के मिले, लेकिन या तो उन्होंने बिजली का कनेक्शन ही नहीं लिया या फिर बिल न चुकाने से उनकी बिजली काट दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों के पास सोलर चार्जर हैं, उन्हें मोबाइल फोन को चार्ज करने पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। शहरी क्षेत्रों में मोबाइल चार्जिंग पर खर्च ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।

मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करने का प्रतिमाह खर्च					
	कोई खर्च नहीं	50 रु. या कम	51–75 रुपये	76–99 रुपये	100 रु. या ज्यादा
परिवारों की संख्या	7	6	4	0	3
(%)	35%	30%	20%	0%	15%
*N=20 परिवारों को मोबाइल फोन चार्ज करने का खर्च वहन करना पड़ता है।					

तालिका 4 : मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करने का खर्च

5.1.3 मोबाइल फोन को लेकर समुदाय की सोच :

मोबाइल की उपयोगिता : शोध के दौरान मोबाइल फोन को लेकर समुदाय की राय को आंकड़ों और गुणवत्तामूलक तथ्य दोनों रूपों में दर्ज किया गया। शोध से मोबाइल के बारे में समुदाय की मिश्रित सोच नजर आई। लोगों ने तीन श्रेणियों में मोबाइल की उपयोगिता बताई – 1. उपयोगी, 2. गैर उपयोगी, 3. कभी–कभी उपयोगी।

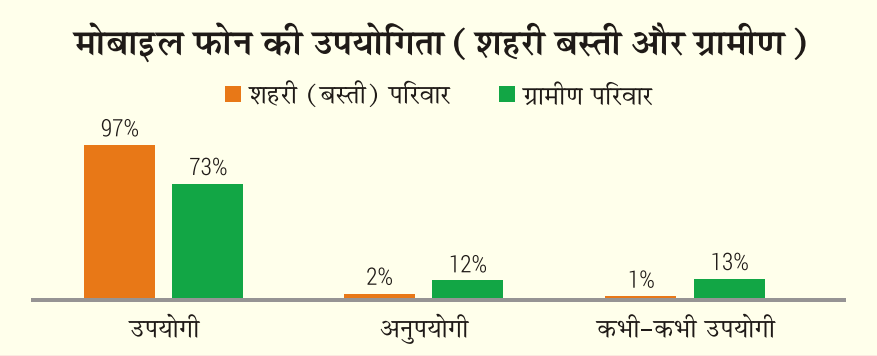

आंकड़े 13 : मोबाइल फोन की उपयोगिता

5.1.4 मोबाइल फोन के उपयोग का उद्देश्य और इसमें आड़े आने वाली समस्याएं :

मोबाइल के उपयोग का उद्देश्य : परिणाम यह बताते हैं कि मोबाइल फोन का उपयोग प्रमुख रूप से सामाजिक संबंधों को कायम रखने में होता है। मोबाइल फोन के दो प्रचलित उपयोग सामने आए। ये हैं– परिजनों और दोस्तों से बात करने में और इनसे संबंधों को बरकरार रखने में। इस तरह बात करने में 97% और रिश्ते बरकरार रखने के मकसद से 81% परिवार मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। मोबाइल रखने वाले परिवारों में 52% अपने मोबाइल का उपयोग मनोरंजन और शिक्षाप्रद प्रयोजनों के लिए भी करते हैं।

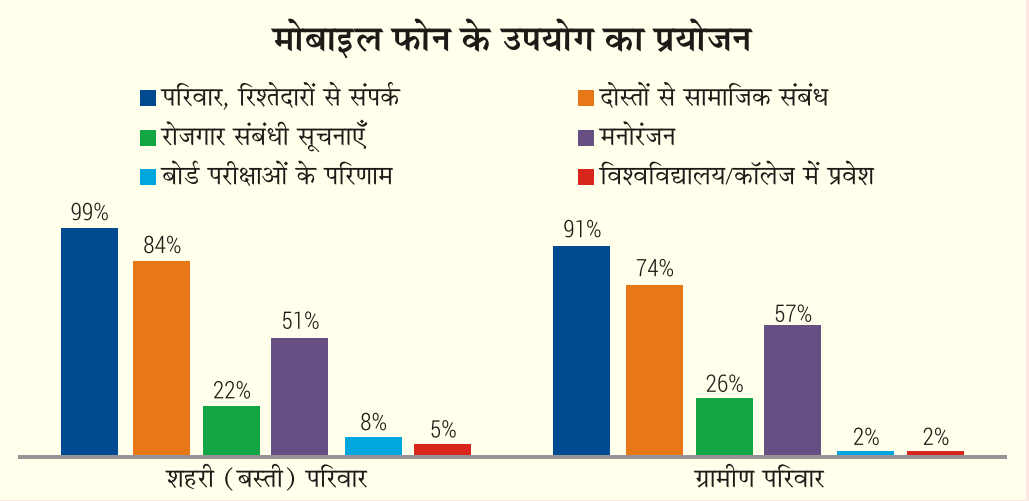

आंकड़े 14 : मोबाइल फोन के उपयोग का उद्देश्य

केवल 23% परिवार मोबाइल का उपयोग कृषि, मनरेगा (ग्रामीण क्षेत्रों में) और निर्माण क्षेत्र में मजदूरी के बारे में (शहरी क्षेत्र), मंडी भाव और पशुधन के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने में करते हैं। स्कूल और उच्च शिक्षा के बारे में मोबाइल से जानकारी हासिल करने वाले परिवार कुछ ही मिले। इसी तरह के रुझान शहरी और ग्रामीण समुदाय में प्रतिशत में आंकड़ों के कुछ बदलाव के साथ मिले।

5.1.5 मोबाइल उपयोग में समस्याएं : मोबाइल उपयोग करने वाले कुल परिवारों में से 16 प्रतिशत को इसके उपयोग में कोई परेशानी नहीं है। बाकी के 84% मोबाइल धारक परिवारों को खराब नेटवर्क, भाषागत, मोबाइल तकनीक के महंगा होने और गैरवाजिब बिल आने जैसी प्रमुख समस्याएं पाई गईं। दिलचस्प बात यह है कि केवल बिजली की उपलब्धता के मामले को छोड़कर मोबाइल उपयोग के मामले में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवारों की समस्याएं तकरीबन एक जैसी हैं।

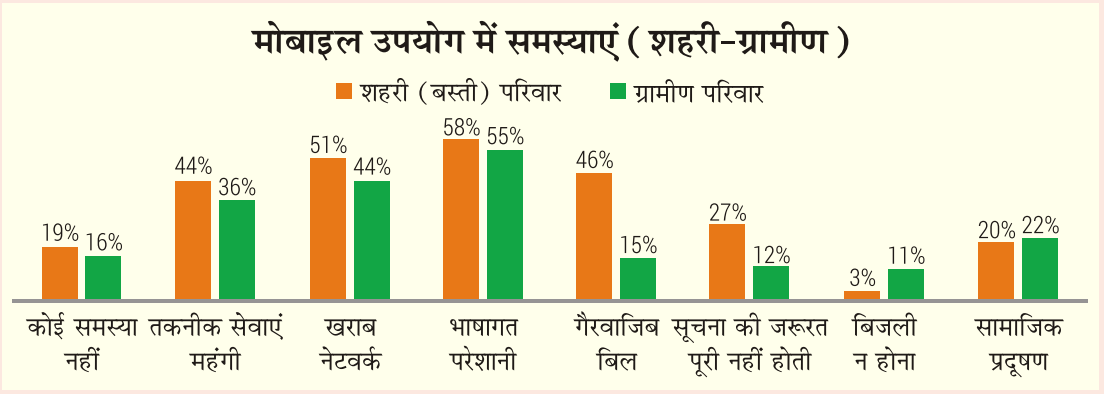

आंकड़े 15 : मोबाइल फोन से जुड़ी समस्याएं

5.2 प्रसारण टेलीविजन और केबल सेवाएं : सैंपल सर्वे में शामिल 1031 परिवारों में से 580, यानी कि 56% परिवारों के पास टीवी मिले। शहरी शोध क्षेत्र में टीवी का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले अधिक पाया गया। शहरी क्षेत्रों में 79% परिवारों के पास टीवी मिले, जबकि 19% ग्रामीण परिवारों के पास टीवी पाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के पास टीवी की कम उपलब्धता का एक प्रमुख कारण 12 में से 5 गांवों में बिजली का न होना रहा। गांवों के जिन परिवारों के पास टीवी नहीं मिले, उनमें से 44% ने बिजली न होने के कारण टीवी नहीं खरीदा था।

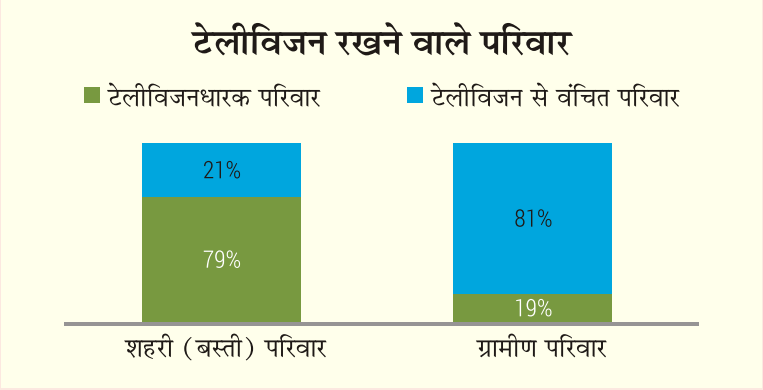

आंकड़े 16 : टेलीविजन धारक परिवार

शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में परिवारों के पास टीवी न होने का सबसे आम कारण टीवी सेट्स का महंगा होना है। इसके बाद डीटीएच व डिजिटल केबल सेवाओं की ऊंची दरें शहरों में टीवी न होने का दूसरा कारण हैं। भाषागत कारण और बिजली कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में सामने आए अन्य कारणों में है। ग्रामीण परिवार टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों को समझ नहीं पाते। शोध क्षेत्र के अधिकांश इलाकों में परिवार स्थानीय बोलियों में बात करते हैं। वे हिंदी भाषा को ठीक से समझ नहीं पाते।

टीवी कनेक्शन के प्रकार (एनालॉग/डिजिटल)

परिवारों के पास मौजूद टेलीविजन कनेक्शन को एनालॉग और डिजिटल दोनों भागों में विभाजित किया गया। एनालॉग कनेक्शन को दूरदर्शन के परंपरागत एंटीना से तार के जरिए जुड़े टीवी और डिजिटल कनेक्शन में सेट टॉप बॉक्स से तार के जरिए केबल या छतरीनुमा एंटीना से जुड़े टीवी के रूप में देखा गया। शोध से पता चला कि टीवी कनेक्शन को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की पसंद अलग-अलग है। शहरों में जहां केबल सेट टॉप बॉक्स लोकप्रिय है, वहीं गांवों में डीटीएच प्रचलित है।

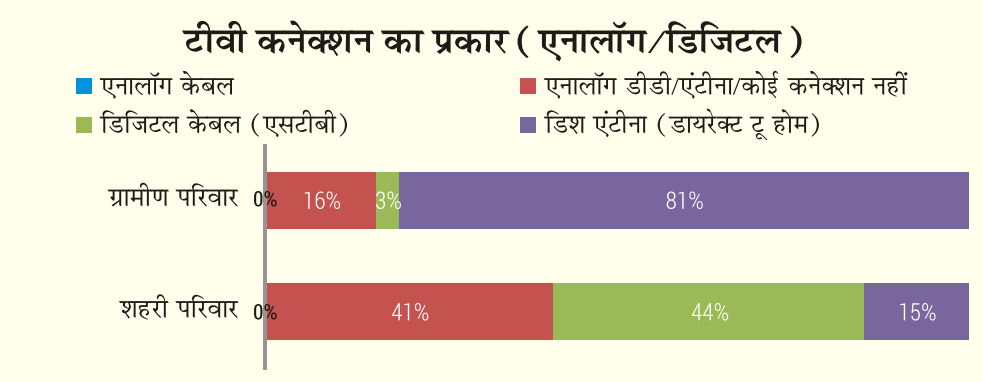

आंकड़े 17 : टेलीविजन कनेक्शन के प्रकार

शहरी शोध क्षेत्र में 41% परिवारों के टीवी में दूरदर्शन ही चलता है। चर्चा में सामने आया कि इन परिवारों के पास पहले परंपरागत केबल कनेक्शन हुआ करता था, जो अब शहरों में डिजिटल हो चुका है। डिजिटल केबल की महंगी दरों का खर्च नहीं उठा पाने से ये परिवार डिजिटल प्रसारण से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी धारक 81% परिवारों ने डीटीएच कनेक्शन ले रखा है, जबकि लगभग 16% परिवार दूरदर्शन देखते हैं, साथ ही कभी-कभार किराए पर डीवीडी प्लेयर लाकर फिल्म देख लेते हैं।.

5.2.1 टीवी की पहुँच और सामाजिक कारक

क. सामाजिक वर्ग और टीवी की पहुँच : शहरी परिवारों में टीवी की घुसपैठ पर परिवार के सामाजिक वर्ग का कोई खास प्रभाव नहीं है। सामान्य वर्ग के 86% परिवारों के पास टीवी है, जबकि अनुसूचित जनजाति के 81% और अनुसूचित जाति के 71% और अन्य पिछड़ा वर्ग के 75% परिवारों के पास टेलीविजन सेट हैं। शोध क्षेत्र के परिवारों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच टेलीविजन की मौजूदगी का कोई विशिष्ट स्वरूप देखने को नहीं मिला। इसके बजाय घर में टेलीविजन होगा या नहीं और होगा तो कैसा होगा, यह तय करने में परिवार की आर्थिक स्थिति की अहम भूमिका पाई गई।

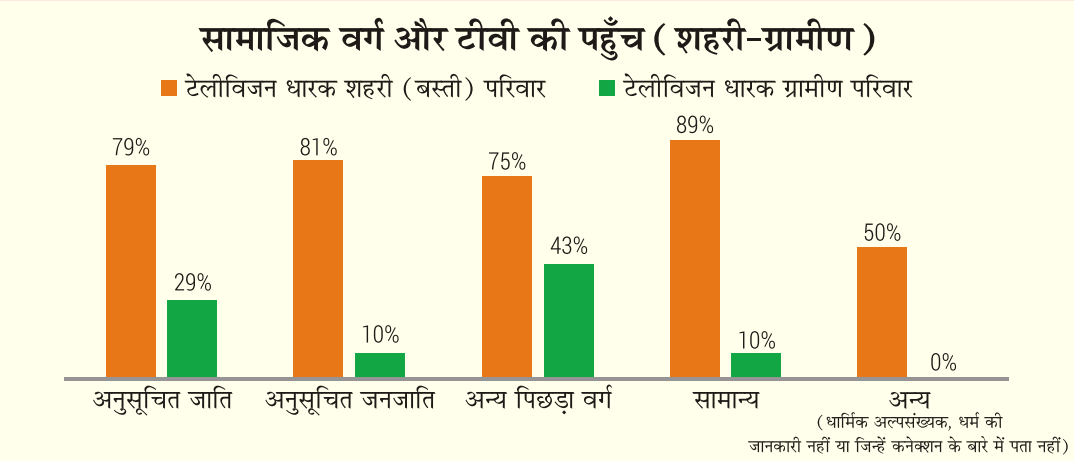

आंकड़े 18 : सामाजिक वर्ग और टेलीविजन की पहुँच

ख. जेंडर और टेलीविजन का उपयोग : टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल पर परिवार के पुरुष सदस्यों का वर्चस्व सामने आया और यह बात शोध क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में देखने को मिली।

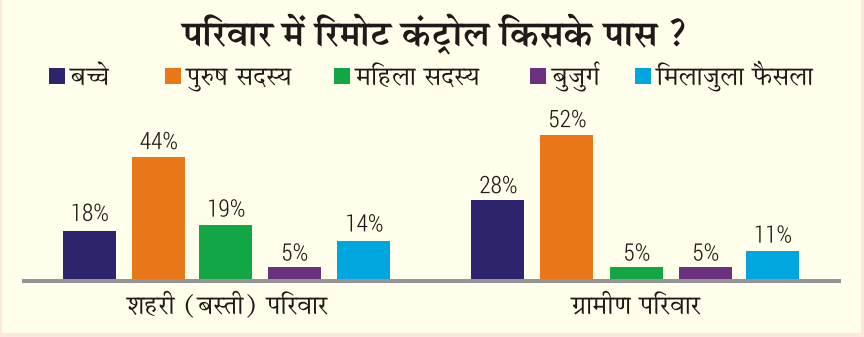

आंकड़े 19 : टेलीविजन के दर्शकों का लैंगिक अनुपात

टेलीविजन पर कौन सा चैनल देखना है, यह तय करने में पुरुषों का दबदबा शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा नजर आया। ग्रामीण इलाकों में 52% तो शहरी क्षेत्रों में 44% परिवारों में टेलीविजन सेट के सामने पुरुषों का वर्चस्व नजर आया। पुरुषों के बाद रिमोट पर कब्जा करने वालों में दूसरे नंबर पर बच्चे थे। कुछ ही परिवारों में रिमोट कंट्रोल का बंटवारा सभी सदस्यों के बीच बराबरी से देखा गया।

5.2.2 टीवी की पहुँच और आर्थिक कारक :

आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों में टीवी की पहुँच ज्यादा है। टेलीविजन धारक परिवारों में सबसे

ज्यादा वे पाए गए, जिनकी प्रतिमाह आय 8000 रुपए से ज्यादा थी। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे टीवी धारक परिवार 8% ही मिले, जिनकी प्रतिमाह आय 1000–2000 के बीच थी। जैसे–जैसे आय का स्तर बढ़ता है, परिवार में टीवी की संख्या भी बढ़ती है।

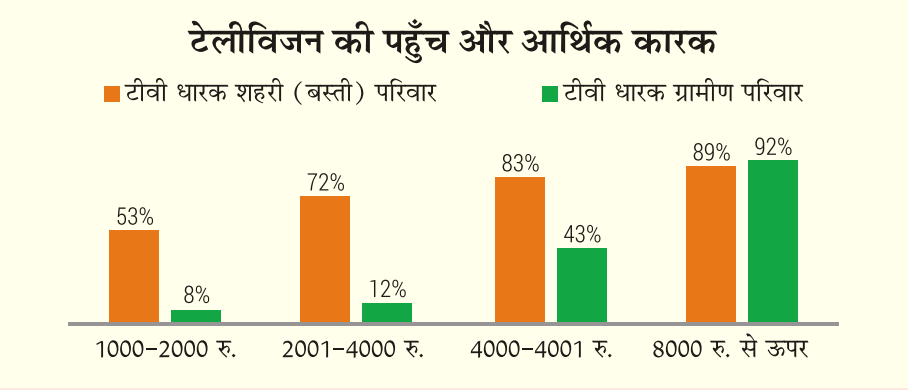

आंकड़े 20 : आमदनी के विभिन्न वर्गों में टेलीविजन की पहुँच

5.2.3 टेलीविजन के उपयोग के बारे में समुदाय के विचार

क. डिजिटल केबल सेवा की गुणवत्ता : शोध से पता चला कि टीवी देखने वाले 64% परिवार डिजिटल केबल सेवा की गुणवत्ता को बेहतर मानते हैं, जबकि 36% के मुताबिक इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। शहरी क्षेत्र में 61% प्रसारण की गुणवत्ता से संतुष्ट थे, जबकि 39% ने इसे खराब कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 13% ने गुणवत्ता को लेकर शिकायत की।

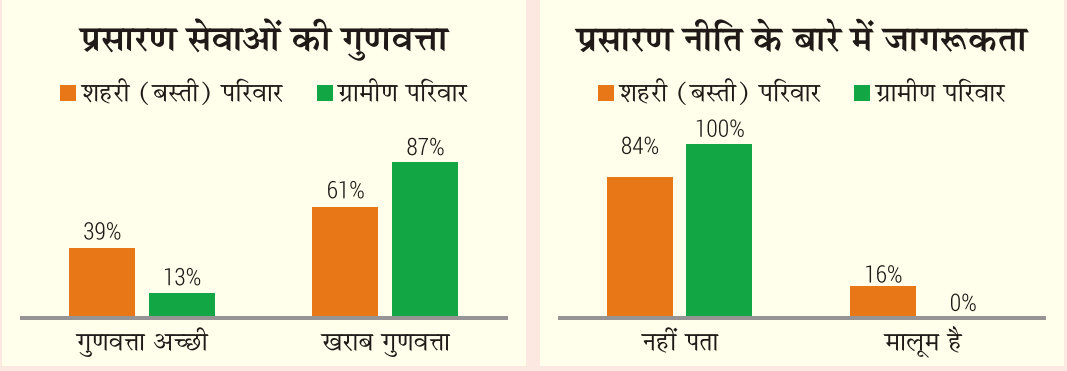

आंकड़े 21 : (बाएं) टेलीविजन प्रसार सेवाओं की गुणवत्ता, (दाएं) प्रसारण नीति को लेकर समुदाय की जानकारी का स्तर

ख. प्रसारण नीति की जानकारी : शोध के दौरान व्यक्तिगत साक्षत्कार और लक्षित समूह चर्चा में पाया गया कि समुदाय को प्रसारण नीतियों के बारे में जानकारी नहीं है। यह बात प्रसारण नीति के नियम–कानूनों से जुड़े सवालों

के जरिए संख्यात्मक तौर पर भी सामने आई। ग्रामीण क्षेत्र में शहरों के मुकाबले स्थिति ज्यादा गंभीर है।

शहरी क्षेत्रों में 84% परिवारों को प्रसारण नीति की कोई जानकारी नहीं थी। वंचित वर्ग में शिक्षा का स्तर कम होने को इसका प्रमुख कारण माना जा सकता है।

5.2.4 डिजिटलीकरण का प्रभाव

सरकार ने सभी तरह के टेलीविजन प्रसारण का डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है। टीवी देखने वालों को या तो डिजिटल केबल या फिर डीटीएच प्लैटफॉर्म से जुड़ना अनिवार्य हो गया है। शोध के अनुसार डिजिटल केबल कनेक्शन की दरें 200–300 रुपए प्रतिमाह के बीच हैं। लेकिन चूंकि डिजिटल सेट टॉप बॉक्स लगवाना एक महंगा सौदा है, इसलिए कई परिवार इसके लिए आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण अभी एनालॉग टीवी प्रसारण देखने पर ही मजबूर हैं।

	शहरी परिवार (%)	ग्रामीण परिवार (%)	कुल परिवार (%)
एनालॉग → डिजिटल	292 (58%)	63 (84%)	355 (61%)
एनालॉग/पुराना केबल → बिना कनेक्शन	177 (35%)	3 (4%)	180 (31%)
टीवी नहीं → टीवी में कोई कनेक्शन नहीं	36 (7%)	9 (12%)	45 (8%)
कुल	505	75	580

तालिका 5 : एनालॉग से डिजिटल की तरफ विचलन

केबल टीवी का डिजिटलीकरण : भोपाल और इंदौर के शहरी क्षेत्रों में पुराने परंपरागत केबल टीवी कनेक्शन का डिजिटलीकरण किया गया है। उपभोक्ताओं को डिजिटल सेट टॉप बॉक्स लगवाना अनिवार्य है। इन क्षेत्रों के कुल 505 परिवारों में 58% ने एनालॉग से डिजिटल केबल टीवी की तरफ रुख किया है। 35% परिवार इसके लिए आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण अपने टेलीविजन सेट को डिजिटल प्रसारण से जोड़ नहीं पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत केबल टीवी की भी पहुँच नहीं है। परिवारों को एनालॉग दूरदर्शन या डीटीएच प्लैटफॉर्म में से किसी एक के जरिए प्रसारण देखना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के उन 84% परिवारों ने जिनके पास पहले दूरदर्शन का प्रसारण आता था, उन्होंने अब डीटीएच प्लैटफॉर्म को अपनाया है, जबकि 4% परिवारों के पास अभी भी एनॉलॉग दूरदर्शन प्रसारित हो रहा है, यानी उनके पास डिजिटल कनेक्शन नहीं है। प्रसारण के डिजिटलीकरण की ऊंची दरों ने शहरी क्षेत्र के कई परिवारों को प्रसारण से वंचित किया है।

5.3 ब्रॉडबैंड–इंटरनेट की पहुँच

5.3.1 समुदाय को इंटरनेट के बारे में जानकारी : समुदाय की इंटरनेट के बारे में जानकारी का आंकलन करने

के लिए प्रश्नावली को एक खास तरह से डिजाइन किया गया था। समुदाय से सहभागितापूर्ण चर्चा के बाद इंटरनेट तकनीक की पहुँच और उपयोग से जुड़े चार शब्दों को समुदाय ने चिन्हित किया। एमपी ऑनलाइन, साइबर कैफे/कियोस्क, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट। शोध में इन्हीं चार शब्दों के बारे में परिवारों की जागरूकता का अध्ययन किया गया। पता चला कि 35% परिवार इंटरनेट शब्द के बारे में जानते हैं। 14% एमपी ऑनलाइन केन्द्रों को जानते हैं, जबकि 9% साइबर कैफे/कियोस्क और 4% ब्रॉडबैंड शब्द के बारे में जानते हैं।

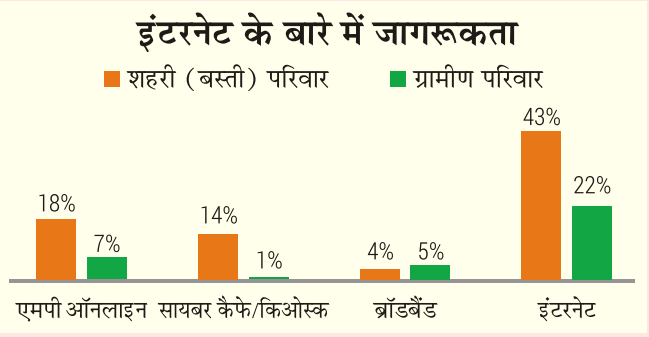

आंकड़े 22 : इंटरनेट के बारे में समुदाय की जानकारी का स्तर

5.3.2 इंटरनेट की पहुँच

- **कम्प्यूटर से जुड़ा इंटरनेट कनेक्शन :** कुल 1031 परिवारों के सैंपल सर्वेक्षण में केवल 14% परिवारों के पास कम्प्यूटर और 13 परिवारों (कुल सैंपल का 1%) के पास वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन पाया गया। शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवार 2% और ग्रामीण क्षेत्र में 1% मिले, जिनके पास कम्प्यूटर और इंटरनेट दोनों मौजूद थे।
- **मोबाइल पर इंटरनेट :** सैंपल सर्वे के 9% परिवार मोबाइल फोन के सहारे इंटरनेट का उपयोग करते हैं। शहरी क्षेत्र में ऐसे 13% परिवार मिले, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार 3% ही पाए गए।
- इंटरनेट उपयोगकर्ता सैंपल सर्वेक्षण में करीब 12% (122) परिवारों में इंटरनेट उपयोगकर्ता मिले। शहरों में 14% और गांवों में 8% परिवारों में इंटरनेट उपयोग करने वाले पाए गए।

	परिवार			
	कुल	कम्प्यूटर	कम्प्यूटर पर इंटरनेट	मोबाइल पर इंटरनेट
शहरी (संख्या)	636	12	12	83
(%)		2%	2%	13%
ग्रामीण (संख्या)	395	2	1	13
(%)		1%	0%	3%
शहरी (संख्या)	1031	14	13	96
(%)		1%	1%	9%

तालिका 6 : इंटरनेट उपयोग

5.3.3 इंटरनेट का उपयोग और सामाजिक कारक

क. सामाजिक वर्ग और इंटरनेट उपयोग : शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के परिवारों में इंटरनेट उपयोग ज्यादा

प्रचलित पाया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के बीच इंटरनेट का उपयोग अन्य वर्गों के मुकाबले ज्यादा प्रचलित पाया गया।

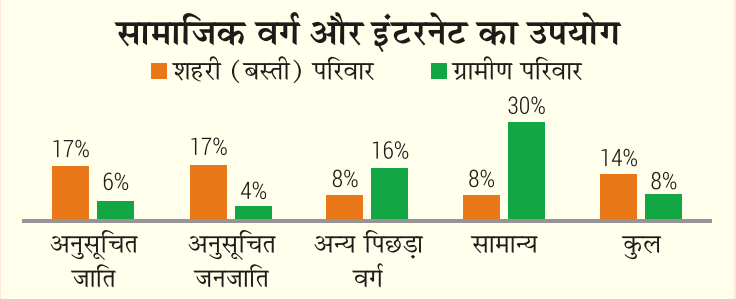

आंकड़े 23 : सामाजिक वर्ग और इंटरनेट का उपयोग

ख. जेंडर और इंटरनेट उपयोग : कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में 13% महिलाएं और 87% पुरुष हैं। लिंगभेद का यह स्तर शहरों और गांवों में एक बराबर है। समुदाय से औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं से पता चला कि समुदाय अभी भी इंटरनेट को अनुपयोगी और महिलाओं के लिए असुरक्षित मानता है। यह भी सामने आया कि महिलाओं का शैक्षणिक स्तर कमजोर है, उनकी जागरूकता और समझ नहीं बनी है और वे इंटरनेट के उपयोग में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं पाती हैं।

इन्टरनेट उपयोगकर्ता			
कुल	पुरुष	महिला	कुल
शहरी	86 (87%)	13 (13%)	99 (75%)
ग्रामीण	29 (88%)	4 (12%)	33 (25%)
कुल	115 (87%)	17 (13%)	132 (100%)

तालिका 7 : इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की लैंगिक स्थिति

ग. आयु समूह और इंटरनेट उपयोग : इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उनके आयु समूह के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता 15-30 के आयु वर्ग में पाए गए।

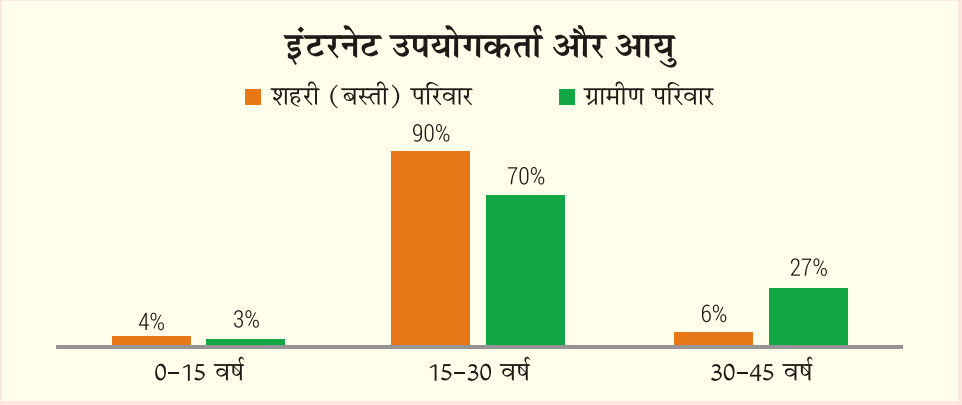

आंकड़े 24 : इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के आयु समूह

5.3.4 इंटरनेट उपयोग और आर्थिक कारक

क. इंटरनेट उपयोगकर्ता परिवार और उनकी आय का स्तर : शोध में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ता परिवारों और उनकी आय का स्तर का आंकलन करने पर शहरी उपयोगकर्ताओं में अस्पष्ट सा कारण सामने आया। शहरों में 33% परिवार 1000–2000 रुपए प्रतिमाह के सबसे निचले आय समूह से नाता रखते हैं। इंटरनेट उपयोग करने वाले केवल 19% परिवारों की प्रतिमाह आय 2000 रुपए से ऊपर पाई गई।

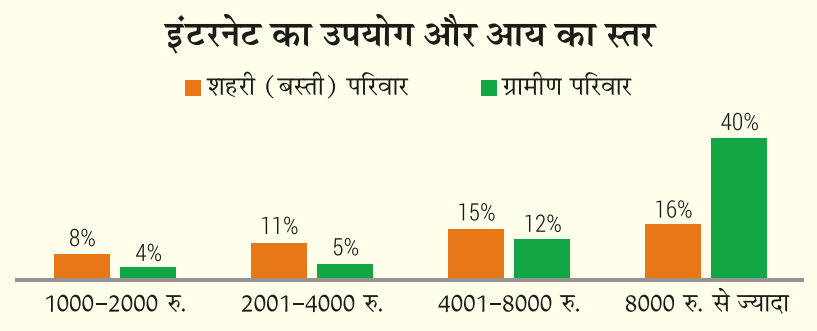

आंकड़े 25 : इंटरनेट उपयोग करने वाले परिवार और उनकी आय का स्तर

ख. इंटरनेट पर खर्च : इंटरनेट उपयोग करने वाले परिवारों में 3% इसके लिए कोई खर्च नहीं करते। वे या तो स्कूल के कम्प्यूटर लैब, दफ्तर, कम्प्यूटर ट्रेनिंग संस्थान या अपने किसी दोस्त के यहां मुफ्त में इंटरनेट उपयोग कर लेते हैं। कुल परिवारों में केवल एक परिवार ही ऐसा मिला, जिसने इंटरनेट पर प्रतिमाह 1000 रुपए खर्च करने का दावा किया। यह सैंपल सर्वेक्षण में शामिल इंटरनेट उपयोग करने वाले परिवारों में इस तकनीक पर सबसे ज्यादा खर्च है। बाकी किसी परिवार में उपयोगकर्ता औसतन 150 रुपए से ज्यादा खर्च इंटरनेट के उपयोग पर नहीं करते पाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पर खर्च करने की क्षमता कम होने और इस तकनीक को लेकर जानकारी में कमी से परिवारों का इंटरनेट उपयोग कम पाया गया।

5.3.5 इंटरनेट उपयोग के स्थान और उपयोग का कारण

उपयोग के स्थान : सर्वेक्षण में इंटरनेट उपयोग के 7 स्थानों को दर्ज किया गया। कुल उपयोगकर्ता परिवारों में 32% (119) उपयोगकर्ता एक से ज्यादा स्थानों पर इंटरनेट उपयोग करते हैं।

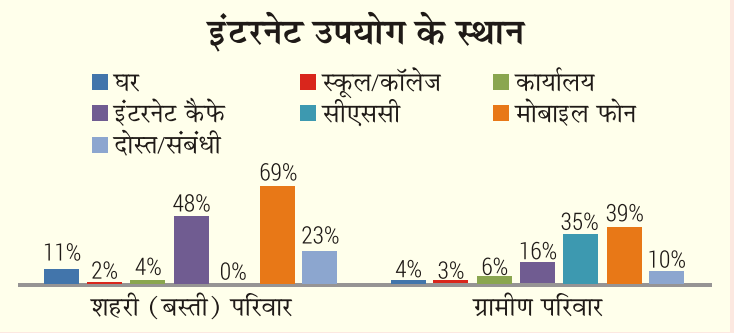

आंकड़े 26 : इंटरनेट का उपयोग कहाँ करते हैं

5.3.6 इंटरनेट उपयोग के कारण : सामाजिक संरचना, शैक्षणिक स्तर, आर्थिक क्षमता, आजीविका के साधन और इंटरनेट की समझ के मामले में शहरी और ग्रामीण समुदाय के बीच विविधता पाई गई। ज्यादातर परिवारों में उपयोगकर्ताओं ने इंटरनेट को मनोरंजन का साधन कहा, जिसके माध्यम से वीडियो और फिल्म डाउनलोड किए जा सकते हैं, उन्हें ऑनलाइन देखा जा सकता है। केवल 4% परिवारों ने कहा कि वे इंटरनेट का उपयोग अपनी शिकायतों/परेशानियों के निवारण में करते हैं।

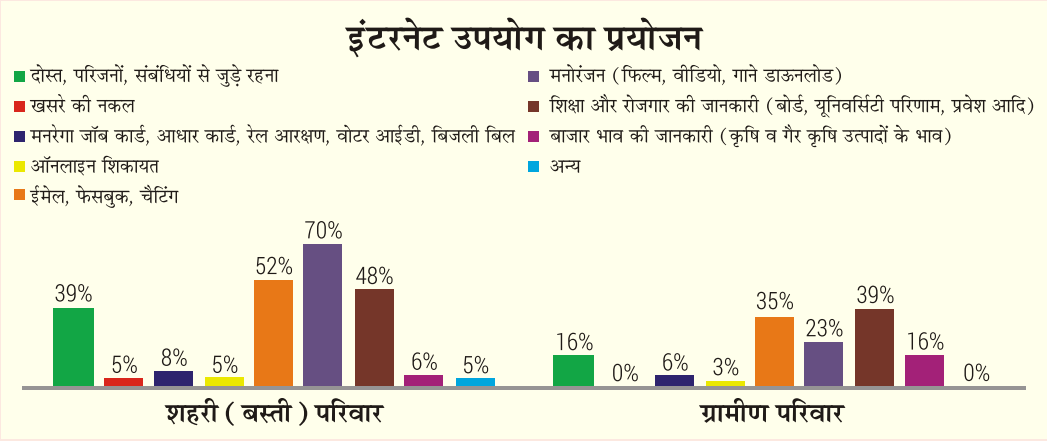

आंकड़े 27 : इंटरनेट उपयोग के कारण

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग तीन प्रयोजनों के लिए पाया गया, सामाजिकता, शिक्षा और रोजगार के साथ मनोरंजन। ग्रामीण परिवारों ने इंटरनेट का उपयोग खेती के बारे में जानकारी के साथ मनरेगा जॉब कार्ड के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भी किया।

5.3.7. इंटरनेट से वंचित परिवार : सैंपल में शामिल कुल 1031 परिवारों में 88% ने इंटरनेट का कभी उपयोग नहीं किया। इसके कारण का आंकलन नीचे दिए गए आंकड़े में है।

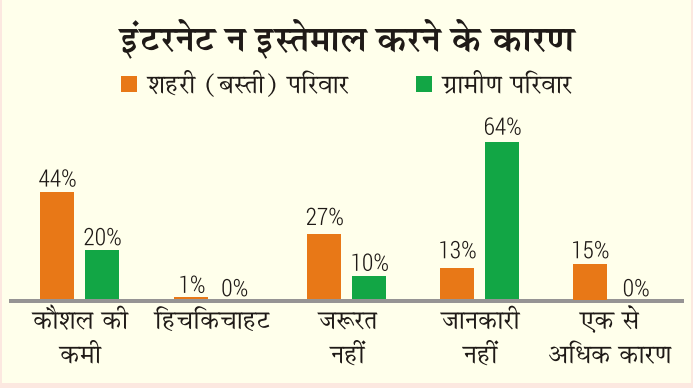

आंकड़े 28 : इंटरनेट का उपयोग न करने का कारण

5.3.8. इंटरनेट के उपयोग से जुड़ी समस्याएं : शहरी क्षेत्रों में कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कम्प्यूटर/लैपटॉप न खरीद पाने को इंटरनेट के उपयोग न करने का सबसे प्रमुख कारण पाया गया। इसके अलावा खराब कनेक्टिविटी और इंटरनेट उपयोग की ऊंची दरें भी प्रमुख कारणों में शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 55% परिवारों ने इंटरनेट उपयोग न करने का कारण ढांचागत इंतजामों के न होने को माना, जबकि खराब कनेक्टिविटी, कमजोर आर्थिक स्थिति और इंटरनेट उपयोग का पर्याप्त कौशल न होना अन्य प्रमुख कारण रहे।

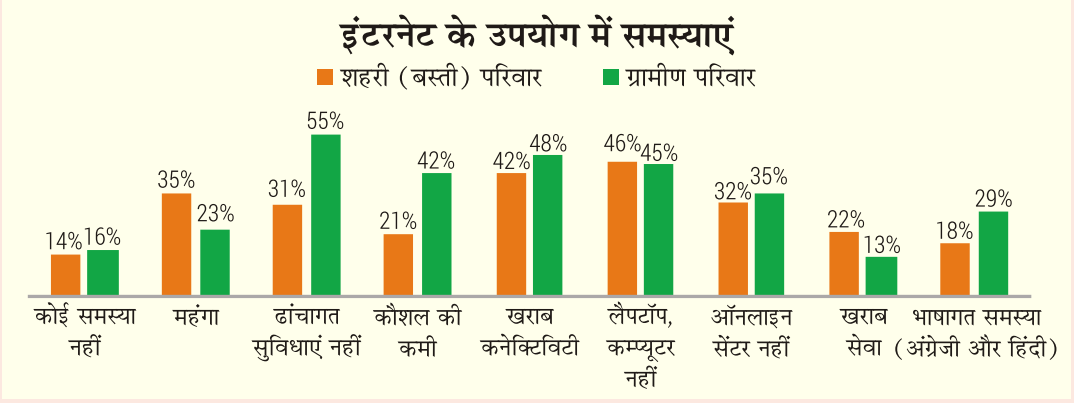

आंकड़े 29 : इंटरनेट का उपयोग और उससे जुड़े मुद्दे

5.3.9 निष्कर्ष : इस शोध कार्य में शहरी बस्तियों और ग्रामीण परिवारों में डिजिटल सूचना संचार के मुख्य रूप से तीन तरह के स्रोत पाए गए। इन तीनों स्रोतों में मोबाइल फोन सबसे प्रचलित साधन है। टेलीविजन और इंटरनेट इसके बाद आता है। सूचना–संचार साधनों के उपयोग के हिसाब से इंटरनेट सबसे कम प्रचलित है। शोध क्षेत्र में चिन्हित सूचना–संचार के तीनों साधनों में से किसी का भी इस्तेमाल परिवार या व्यक्ति विशेष की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है और यह संसाधन तक पहुंच में संभावित रुकावट भी है।

आर्थिक स्थिति के बाद डिजिटल तकनीक के उपयोग को प्रभावित करने में समुदाय और परिवार की सामाजिक–सांस्कृतिक सोच एक बड़ा कारक है। सूचना–संचार के डिजिटल स्रोतों का उपयोग करने में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले कम है। इस तरह की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाले की उम्र भी काफी महत्व रखती है। शोध में पाया गया कि तीनों तरह के सूचना–संचार साधन 15 से 36 साल की आयु समूह के बीच लोकप्रिय हैं।

सामाजिक–आर्थिक बाधाओं के साथ शोध क्षेत्र के दायरे में आने वाले वंचित समुदाय तक ढांचागत साधनों की कमी भी उन्हें डिजिटल साधनों के प्रति जागरूक और जानकार समाज का हिस्सा बनने में एक गंभीर रुकावट के रूप में सामने आई है। शोध क्षेत्र के अंतर्गत पांच गांवों को अभी भी बिजली आने का इंतजार है। ऐसे में यह जरूरी है कि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं और डिजिटल तकनीक तक वंचित समुदाय की पहुंच में आ रहीं रुकावटों को दूर करने के साथ ही सरकार इसके लिए पर्याप्त क्रियाशील ढांचा खड़ा करे।

चरण-3 : लिंग आधारित सर्वेक्षण

1. उद्देश्य :

कम्प्यूटर सूचना-संचार तकनीक तक महिलाओं की पहुंच में सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक रुकावटों को जानना और इसके पीछे के कारणों और फैलाव को पहचानना।

2. सैंपल की इकाई :

महिला उत्तरदाता

3. सैंपल का आकार :

कुल 540 महिलाएं, जिनसे लैंगिक भेदभाव आधारित सवालों के साथ अलग से बात की गई।

4. शोध के परिणाम

4.1 डिजिटल संचार : महिलाओं की स्थिति

वित्तीय समावेशीकरण को गहराई से जानने के लिए किए गए इंटर मीडिया ट्रैकर सर्वे[5] में पाया गया कि भारत में 94 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ताओं में महिलाओं की संख्या आधे से भी कम है। भारत में मोबाइल उपयोगकर्ता 94 करोड़ लोगों में 68% पुरुष और 31% महिलाएं हैं। विशेषकर उत्तरी राज्यों में मोबाइल फोन के स्वामित्व के मामले में स्त्री और पुरुषों के बीच बड़ा फासला है। 'मोबाइल फोन्स : अ टूल फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज'[6] नाम के एक परिपत्र में एमएसबीसी इंडिया ने कहा भारत में मोबाइल फोन रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू में एक तकनीकी साधन से आगे बढ़कर सामाजिक उपयोग की वस्तु बन चुका है।

भारत में 20 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं (वायरलाइन और वायरलैस) में महिलाओं की प्रतिभागिता केवल 39 फीसदी है। कभी भी, कहीं भी संपर्क के साधन के रूप में मोबाइल फोन ने लोगों की जिंदगी को आसान किया है। इसके सहारे लोगों की सूचनाओं और सामाजिक, आर्थिक हकदारियों तक बेहतर पहुँच बनी है। आईएमआरबी के अनुसार मध्यप्रदेश में 5.54 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ताओं में मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ता दो करोड़ से भी कम हैं। इनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों के हैं।

4.2 शोध क्षेत्र का जननांकीय विवरण

जनगणना 2011[7] के आंकड़े बताते हैं कि देश में 65 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं निरक्षर हैं। इस मामले में मध्यप्रदेश का स्थान कहीं नीचे है, जहां महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम 60 प्रतिशत है। अगर हम शहर और गांवों के बीच

[5] India : Financial services use and immerging digital pathways FII tracker survey
[6] http://msbcindia.org/wp-content/uploads/2014/02/A-Working-paper-book.pdf
[7] http://censusindia.gov.in/2011census/censusinfodashboard/stock/profiles/en/IND023_Madhya%20Pradesh.pdf

की असमानता को देखें तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 52.43 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं। मध्यप्रदेश जैसे एक ऐसे राज्य में जहां तकरीबन आधी महिलाएं निरक्षर हों, डिजिटल तकनीक की उन तक पहुँच सुनिश्चित कर न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण वंचित परिवारों की क्षमता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे बेहतर कनेक्टिविटी और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की मांग में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी।

अगर हम वायरलेस और वायरलाइन दोनों तरह की सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को देखें तो पाएंगे कि उनका प्रतिनिधित्व केवल 39 प्रतिशत है। आईएमआरबी के अनुसार मध्य प्रदेश में 5.54 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ताओं में मोबाइल पर इंटरनेट चलाने वालों की संख्या 1.7 करोड़ है। इनमें अधिकांश शहरी क्षेत्रों के हैं।

शोध के तहत मध्यप्रदेश के पांच जिलों में दो शहरों, भोपाल और इंदौर की 6 बस्तियों और पन्ना, झाबुआ और डिंडोरी जिलों के कुल 12 गांवों में से प्रत्येक में 30 महिलाओं को यादिच्छिक रूप से चुना गया और उनसे सूचनाओं की जरूरत, उपलब्धता, सूचनाओं के स्रोत, डिजिटल सूचना–संचार के साधनों जैसे मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल प्रसारण साधनों के उपयोग से जुड़े सवालों के जरिए उनकी पहुंच में रुकावटों को जानने की कोशिश की गई। इस तरह शोध की कुल 18 ईकाइयों से कुल 360 महिलाओं को सर्वे के लिए चुना गया।

4.3 शैक्षणिक स्तर :

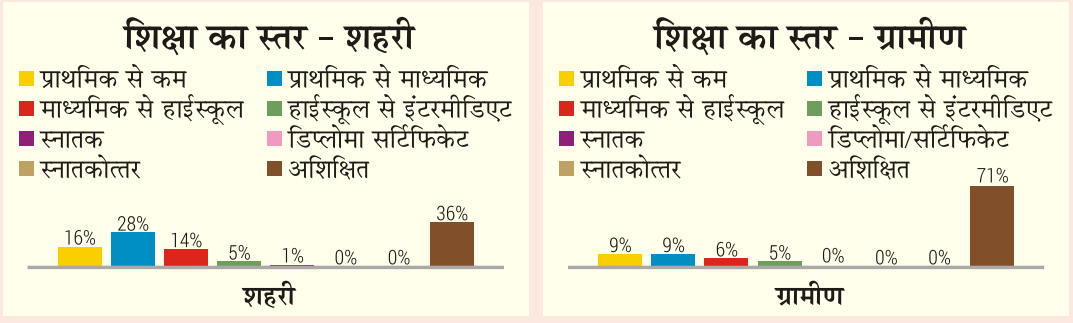

आंकड़े 30 : महिला उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

जनगणना 2011 के अनुसार, मध्यप्रदेश में स्त्री साक्षरता की दर 60% है। शहरी क्षेत्रों में वंचित वर्ग की 36% महिलाएं अशिक्षित पाई गईं। माध्यमिक स्तर तक शिक्षित महिलाएं 28% मिलीं। ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से ज्यादा महिलाएं अशिक्षित पाई गईं, जबकि 23% ने हाईस्कूल तक की शिक्षा हासिल की थी।

4.4 सामाजिक वर्गों का विवरण :

शहरी बस्तियों में अनुसूचित जाति की महिलाएं ज्यादा रहीं। इंदौर के भील पलटन बस्ती में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का प्रतिनिधित्वि 90% से अधिक था। अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की नुमाइंदगी 61% रही। ग्रामीण क्षेत्रों में 76% से ज्यादा महिलाएं अनुसूचित जाति वर्ग से थीं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व 17% से अधिक रहा।

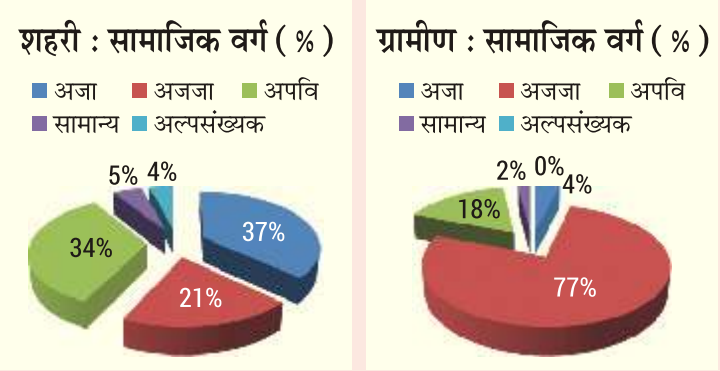

आंकड़े 31 : सामाजिक वर्ग

4.5 सूचना के स्रोत

डिजिटल सूचना–संचार साधनों के उपयोग में असमानता के पीछे दो कारक प्रमुख हैं– कौशल और पहुँच की कमी। जब तक समुदाय की डिजिटल तकनीक तक पहुँच नहीं होगी, तब तक उनका तकनीकी कौशल विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक इसी तरह जब तक समुदाय की डिजिटल संचार साधनों के उपयोग की तकनीकी क्षमता विकसित नहीं होगी, तब तक उनकी पहुँच में भी रुकावट आएगी।

शिक्षा व्यक्ति को इस बदलती दुनिया के बारे में जानकार बनाता है। यह हमें सूचना के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जानने के अधिकार जैसी हकदारियों को हासिल करने की शक्ति देता है। हालांकि, यह कुछ बातों पर निर्भर है, जैसे समुदाय में सूचना के स्रोत, संचार का माध्यम और सूचना प्राप्त करने के सबसे आसान तरीके। भोपाल और इंदौर में जहां दो में से एक बस्ती शहर के बीचों–बीच स्थित है। केवल भोपाल में जाटखेड़ी और इंदौर में राहुल गांधी नगर को मुख्य शहर से बाहर बसाया गया है। दोनों बस्तियों में टेलीविजन और मोबाइल फोन संचार का सबसे आसान साधन है।

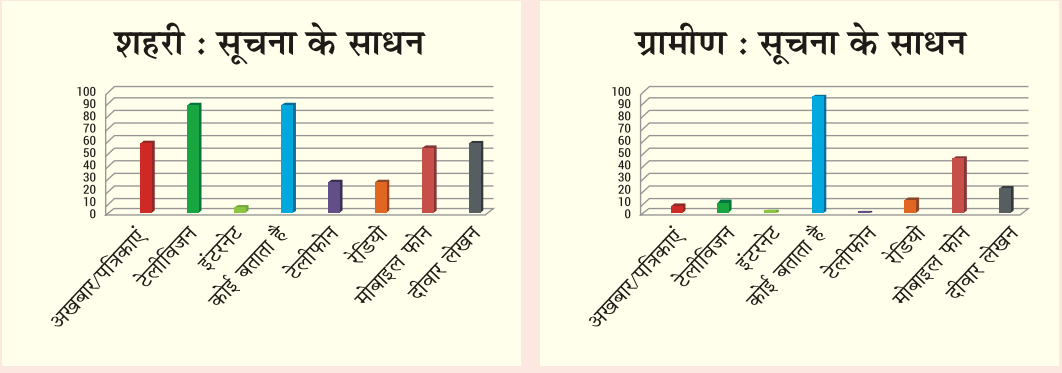

आंकड़े 32 : सूचना के स्रोत

लगभग 89% महिलाओं ने टेलीविजन को सूचना प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम बताया, जबकि मोबाइल फोन 53% के साथ दूसरे नंबर पर रहा। शहरी क्षेत्रों में समाचार पत्रों के जरिए सूचना प्राप्त होने की बात 57% महिलाओं ने कही, जबकि 88% ने कहा कि उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन इतनी ही महिलाओं को कोई आकर जानकारी देता है। मोबाइल फोन ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्राप्ति का दूसरा लोकप्रिय व आसान साधन है।

4.6 सूचना के साधनों की जरूरत

डिजिटल तकनीक जिस तेजी से प्रगति कर रही है, उससे इसके उपयोग के कौशल और नवीनतम तकनीक को अपनाने की आर्थिक क्षमता का बोझ लगातार बढ़ रहा है। यह हमारे समाज में कहीं न कहीं वंचितपन, बहिष्कार और वहनशीलता के मामले में सामाजिक विभाजन को और विस्तृत किया है। मिसाल के लिए भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में जहां टेलीविजन चैनलों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 2016 के आखिर में यह देश के तकरीबन सभी शहरों में पूरी हो जाएगी। डिजिटल टेलीविजन प्रसारण की इस नई तकनीक में घर का टेलीविजन एक सेट टॉप बॉक्स के जरिए या तो डिजिटल केबल या फिर डिश एंटीना से जुड़ा होता है, जिसे डायरेक्ट टू होम कहा जाता है। लेकिन यह तकनीक परंपरागत एनालॉग केबल या टीवी एंटीना तकनीक के मुकाबले कहीं महंगी और जटिल है, क्योंकि इसमें एक सेट टॉप बॉक्स और रिमोट कंट्रोल की अलग से जरूरत पड़ती है। इस वजह से टेलीविजन प्रसारण की इस आधुनिक तकनीक ने फिलहाल शहरों के उन वंचित परिवारों को टेलीविजन प्रसारण सेवाओं से महरूम कर दिया है, जो पहले अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर केबल प्रसारण प्राप्त कर लेते थे। अब उन्हें डिजिटल टीवी प्रसारण के लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ रहा है।

यह अभी एक ऐसी शुल्क प्रणाली है, जिसका देश भर में एक समान नियमन नहीं हो पाया है। शहरी क्षेत्र की 40 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्हें सूचना साधन के रूप में टेलीविजन की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है और इसके लिए उन्होंने डिजिटल सेट टॉप बॉक्स को सबसे जरूरी बताया। मोबाइल फोन की जरूरत 34% और सूचना साधन के रूप में इंटरनेट की जरूरत 19% महिलाओं ने बताई। ग्रामीण क्षेत्रों में 55% महिलाओं ने कहा कि उन्हें

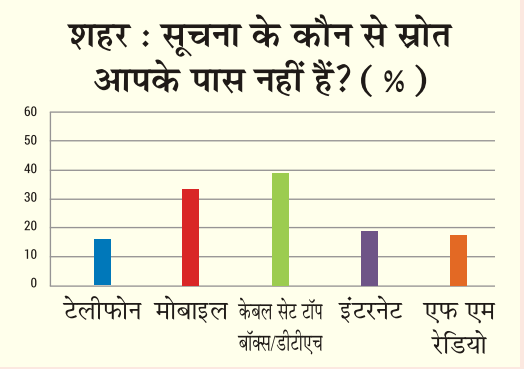

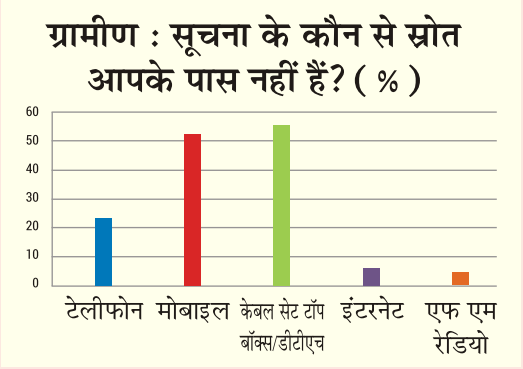

आंकड़े 33 : सूचना के किस स्रोत का अभाव है ?

डिजिटल टीवी की सबसे ज्यादा जरूरत है, जबकि 52% ने मोबाइल फोन की जरूरत महसूस की। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और मोबाइल फोन की मांग काफी ज्यादा पाई गई।

शहरी क्षेत्रों में 29 प्रतिशत महिला उत्तीरदाताओं ने कहा कि उनके टेलीविजन में कोई भी डिजिटल कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि ये परिवार केवल दूरदर्शन का राष्ट्रीय चैनल ही देख पा रहे हैं, जो अभी भी एनालॉग प्रसारण कर रहा है।

4.7 व्यवसाय और आजीविका

ग्रामीण आदिवासी समुदाय में महिलाएं घर से बाहर निकलकर खेतों में या मजदूरी के काम में पुरुषों के साथ ही बराबर की भागीदारी करती हैं। शोध के दौरान 93% ग्रामीण महिलाएं कामकाजी पाई गईं, जबकि शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 62 रहा।

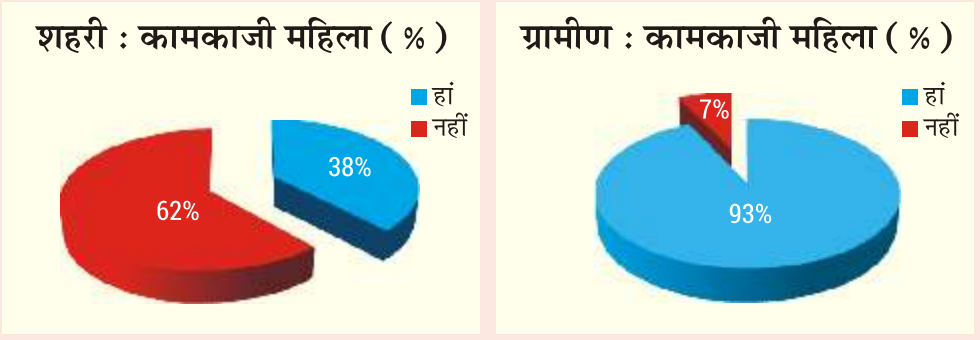

आंकड़े 34 : कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाएं

5. संचार के साधन

5.1 संचार साधनों के उपयोग की स्थिति

शहरों में महिलाएं चाहे वे घर से बाहर निकलकर काम करें या फिर परिवार की देखभाल, आपस में जुड़े रहने का सबसे आसान माध्यम मोबाइल फोन है। शहरी क्षेत्र की 6 बस्तियों में 85% महिलाएं मोबाइल फोन की उपयोगकर्ता हैं। भोपाल के जाटखेड़ी और इंदौर के राहुल गांधी नगर में मोबाइल उपयोगकर्ता महिलाएं 90% से भी अधिक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल उपयोगकर्ता महिलाएं 61% ही मिलीं।

शहरी क्षेत्रों में 39% महिलाएं अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करती हैं, जबकि 57% महिलाओं ने कहा कि वे परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए रखे गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर लेती हैं। शहरी बस्तियों की 4% महिलाओं को मोबाइल से संपर्क साधने के लिए किसी अन्य की सहायता लेनी पड़ती है। भोपाल की कृष्णा नगर बस्ती में सबसे ज्यादा 46% महिलाओं के पास मोबाइल फोन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 61% महिलाएं मोबाइल फोन का उपयोग करती हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती

हैं। शोध में केवल 20% ग्रामीण महिलाओं के पास मोबाइल फोन मिले, जबकि 19% महिलाओं ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे किसी से मोबाइल फोन मांगकर इस्तेमाल कर लेती हैं।

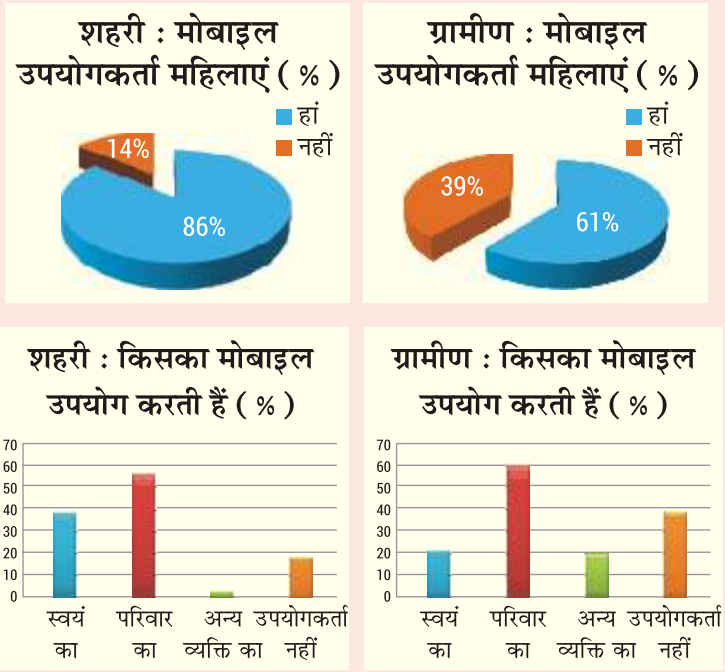

आंकड़े 35 : मोबाइल फोन, उपयोगकर्ता और किसका मोबाइल

5.2 मोबाइल का उपयोग क्यों जरूरी लगता है?

शहरी शिक्षित, सशक्त महिला के लिए मोबाइल केवल एक संपर्क का ही माध्याम नहीं है। वे सबसे पहले मोबाइल फोन का उपयोग सीखती हैं और फिर उसे अपनी भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती हैं। वे अपनी पसंद-नापसंद को बेरोकटोक अपनी इच्छा से किसी के साथ भी साझा कर सकती हैं। यह अभिव्यक्ति वीडियो, फोटो जैसे किसी भी रूप में हो सकती है। लेकिन अभिव्यक्ति के इन हरेक रूपों में स्त्री की स्वतंत्रता, उसकी पहचान और विभिन्न मुद्दों पर उसकी सोच जाहिर होती है। इसके अलावा मोबाइल फोन मनोरंजन का साधन भी है।

शिक्षित कामकाजी शहरी महिला के लिए मोबाइल फोन केवल संपर्क साधने का ही माध्यम भले न हो, लेकिन शहरी वंचित वर्ग की महिला के लिए यह परिवार और संबंधियों से जुड़े रहने का सबसे अच्छा और आसान माध्यम है। शोध

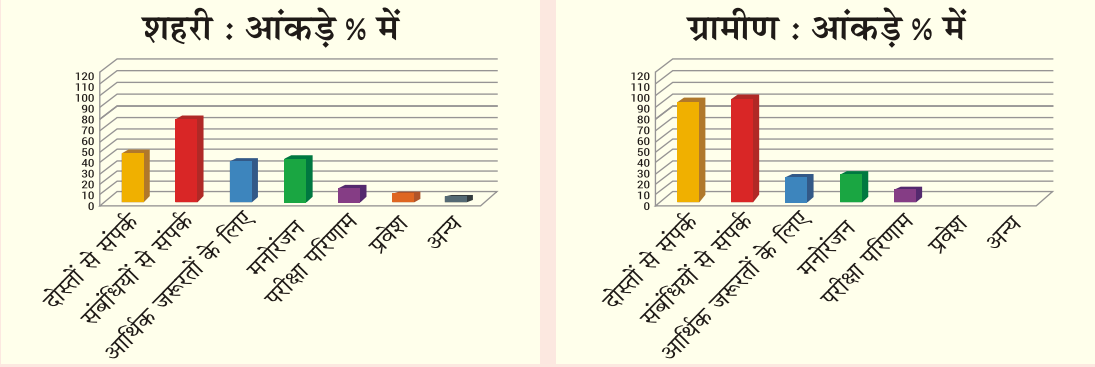

आंकड़े 36 : मोबाइल फोन का उपयोग क्यों जरूरी?

में पाया गया कि 75 फीसदी शहरी वंचित वर्ग की महिलाएं परिजनों, संबंधियों और दोस्तों से संपर्क साधने के लिए मोबाइल फोन उपयोग करती हैं। 37% महिलाओं ने मोबाइल फोन को मनोरंजन का साधन बताया, जबकि 35% शहरी वंचित वर्ग की महिलाओं ने कहा कि वे आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करती हैं। शहरी बस्तियों की इन महिलाओं की आर्थिक जरूरतों में रोजगार के विकल्प सबसे अहम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधियों से संपर्क साधने और दोस्तों से बात करना मोबाइल के उपयोग के सबसे प्रचलित कारणों में हैं। मोबाइल फोन की मदद से आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका ई–कॉमर्स/ ई–बैंकिंग या इस तरह की वे सेवाएं हो सकती हैं, जिससे हम अपनी आवश्यकता की चीजें ऑनलाइन मंगाते हैं। लेकिन इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। हालांकि इसमें कुछ छिपी हुई रुकावटें भी हैं, जैसे इंटरनेट की लागत, इसका अधिकतम उपयोग करने की व्यक्तिगत क्षमता और अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल की आजादी वगैरह। ऐसे में मोबाइल फोन पर किफायती दरों में उपलब्धत मूल्यवर्द्धित सेवाओं (वैस) को भी नौकरियों, ताजा खबरों और वित्तीय सेवाएं पाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

5.3 मोबाइल उपयोग का स्वरूप :

अगर कोई आपसे यह सवाल करे कि आपने पिछले एक हफ्ते में कितनी बार मोबाइल फोन का उपयोग किया तो आपके लिए जवाब देना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप बात करने, मैसेजिंग, संगीत सुनने और सोशल मीडिया पर फोटो–वीडियो अपडेट्स भेजने का काम लगातार करते ही हैं। मोबाइल फोन का लगातार उपयोग व्यक्ति विशेष की उस तक पहुंच पर निर्भर करती है। सर्वेक्षण में महिलाओं से पूछा गया कि उन्होंने बीते 6 माह में कितनी बार मोबाइल फोन का उपयोग किया है शहरी और ग्रामीण वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए भी इस सवाल का तुरंत जवाब देना आसान नहीं था, क्योंकि आपका मोबाइल फोन का उपयोग आपकी पहुंच पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। शहरी क्षेत्र में वंचित वर्ग की 38% महिलाओं के पास ही मोबाइल फोन उपलब्ध हैं, जबकि 57% महिलाएं परिवार के लिए उपलब्ध मोबाइल फोन का उपयोग करती हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि करीबन 58% महिलाओं ने लगातार मोबाइल फोन का उपयोग किया, जबकि 22% ने कहा कि वे कभी–कभार ही इसका इस्तेमाल कर पाईं। ग्रामीण क्षेत्र में जहां 20% महिलाओं के पास ही मोबाइल फोन उपलब्ध हैं, 50% से ज्यादा महिलाओं का कहना था कि वे कभी–कभार ही मोबाइल का उपयोग कर पाईं।

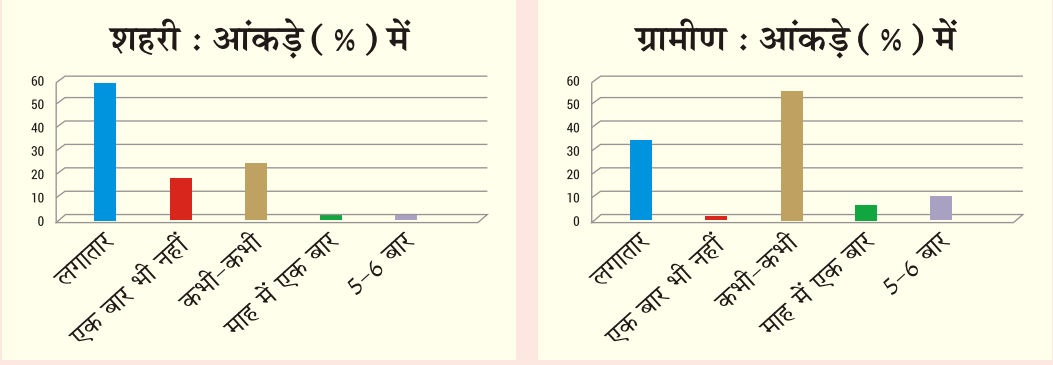

आंकड़े 37 : बीते 6 माह में आपने मोबाइल का कितनी बार उपयोग किया?

5.4 मोबाइल उपयोग : रुकावटें

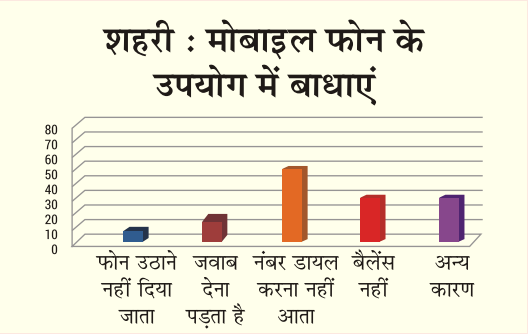

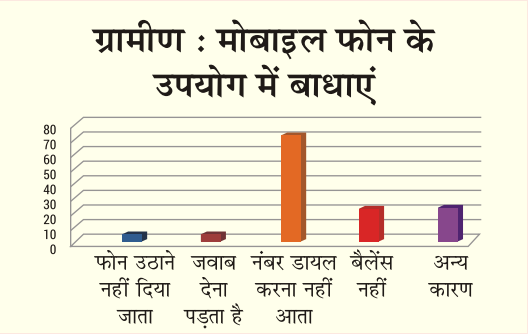

आंकड़े 38 : मोबाइल फोन के उपयोग में बाधाएं

शहरी क्षेत्र की 49% महिलाओं के सामने नंबर डायल करना सबसे बड़ी रुकावट थी। दूसरी रुकावट मोबाइल में बैलेंस न होना रहा। TRAI दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार देश में 95% मोबाइल उपयोगकर्ता प्री-पेड हैं। ऐसे में शहरी क्षेत्रों की 29% महिलाओं के सामने मोबाइल बैलेंस न होना परिवार के अन्या सदस्यों पर उनकी निर्भरता की ओर संकेत करता है। ग्रामीण क्षेत्र में 72% महिलाओं ने कहा कि उन्हें मोबाइल पर नंबर डायल करना नहीं आता, जबकि 21% ने बैलेंस न होने की बात कही।

शहरी क्षेत्र की 15% महिलाओं ने कहा कि मोबाइल के उपयोग पर उन्हें परिवार के सदस्यों को बताना पड़ता है कि किसका फोन था और क्या बात की गई।

5.5 मोबाइल पर खर्च किसके हाथ में

शहरी क्षेत्र की 26% महिलाओं ने कहा कि मोबाइल उपयोग के एवज में होने वाले खर्च को वे खुद वहन करती हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की 65% महिलाएं मोबाइल उपयोग पर खर्च के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर हैं। ग्रामीण

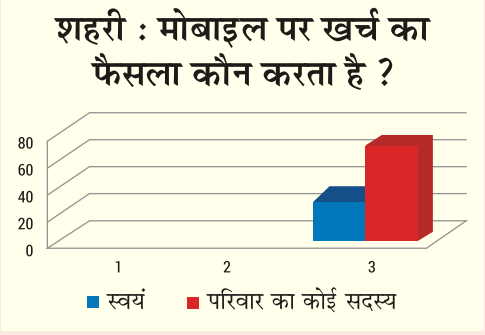

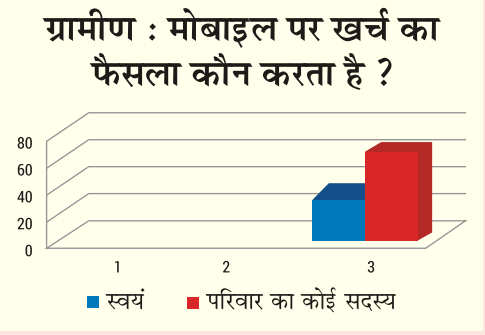

आंकड़े 39 : मोबाइल पर खर्च का नियंत्रण

क्षेत्र की 35% महिलाओं ने कहा कि वे मोबाइल उपयोग का खर्च खुद वहन कर लेती हैं। यह ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सक्षमता की ओर भी इशारा करता है, जिसका एक बड़ा कारण आजीविका में उनकी सहभागिता है।

6 इंटरनेट- अभी भी 'बड़ी' चीज है

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI[8] के अनुसार भारत में तकरीबन 26 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में वायरलाइन यानी मॉडम से इंटरनेट चलाने वालों की संख्या 1.8 करोड़ से कुछ अधिक ही है। ये वे उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 512 केबीपीएस की न्यूनतम स्पीड मिलती है। बाकी 24 करोड़ लोग अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट चलाते हैं, जिन्हें स्पीड में उतार-चढ़ाव का लगातार सामना करना पड़ता है।

इस प्रकार देश की इंटरनेट उपयोगकर्ता 19 फीसदी आबादी में से केवल 4% के पास ही मॉडम कनेक्शन उपलब्ध है। आईएमएआई-आईएमआरबी[9] की रिपोर्ट कहती है कि देश में इंटरनेट उपयोगकर्ता महिलाओं की संख्या 2 करोड़ से कुछ अधिक हो गई है। हालांकि यह देश के महानगरों और बड़े शहरों के आंकड़े हैं। शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली स्कूली छात्राओं की संख्या तकरीबन 30 लाख के आसपास है, जबकि गैर कामकाजी महिलाओं की संख्या 18 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 58 लाख को पार कर गई है। शहरी क्षेत्रों में 60 फीसदी कामकाजी और 47 फीसदी गैर कामकाजी महिलाएं इंटरनेट का रोजाना उपयोग करती हैं।

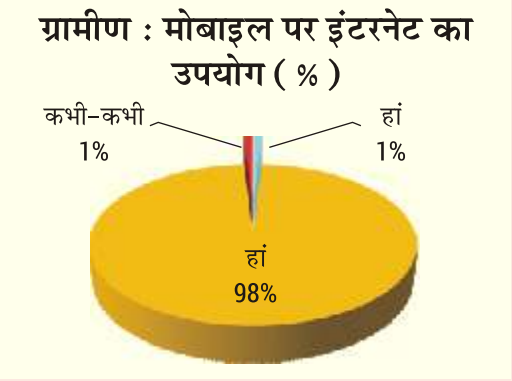

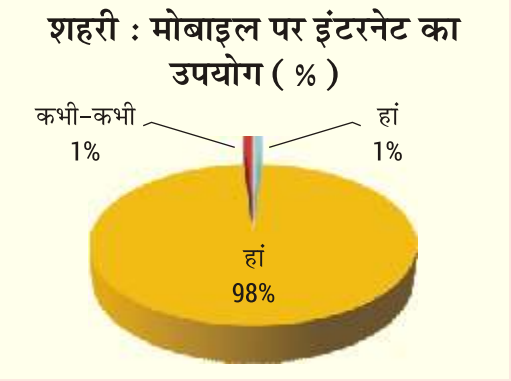

आंकड़े 40 : मोबाइल फोन पर इंटरनेट का उपयोग

6.1 इंटरनेट का उपयोग

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अगस्त 2014 तक 5.66 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता हैं, जिनमें ग्रामीण उपयोगकर्ता 15-20 प्रतिशत के आसपास हैं। बाजार के जानकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1.7 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो मुख्य रूप से शहरों से हैं। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के आंकड़े सर्किल पर आधारित होते हैं। इनका जेंडर आधारित वर्गीकरण नहीं होता। शोध के दौरान शहरी बस्तियों की 97%

[8] दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 2014

[9] http://www.iamai.in/press release_detail.aspx?nid=3494&NMonth=11&NYear=2014

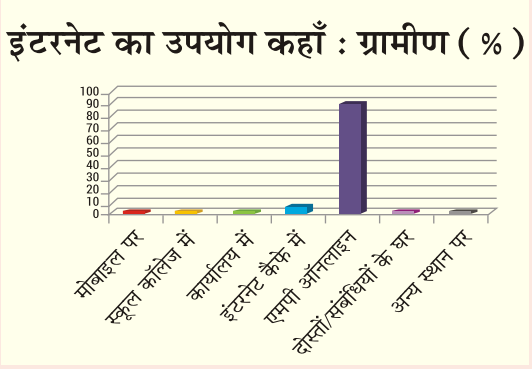

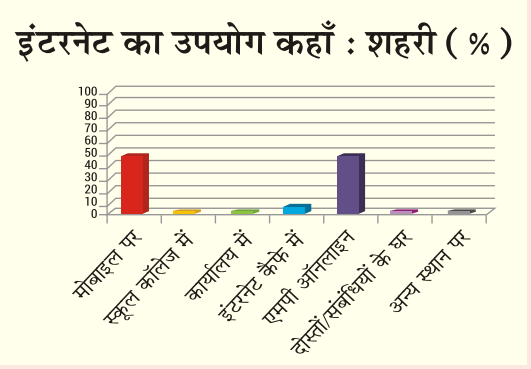

आंकड़े 41 : इंटरनेट उपयोग करने के स्थान

महिलाओं ने कहा कि वे मोबाइल फोन पर इंटरनेट का उपयोग नहीं करती हैं। इनमें से 50% ने हालांकि इंटरनेट के बारे में सुना जरूर है। शहरी बस्तियों की 180 महिलाओं में से केवल 3% महिलाएं ही वायरलाइन यानी मॉडम आधारित इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 98% महिलाओं का कहना था कि उन्होंने इंटरनेट का कभी उपयोग नहीं किया।

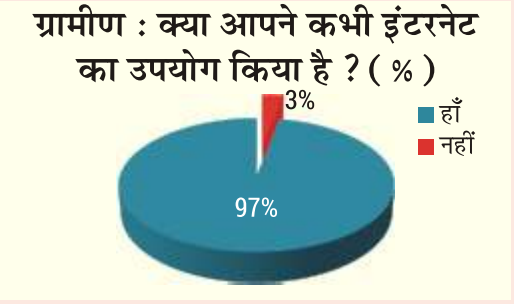

आंकड़े 42 : इंटरनेट का उपयोग

6.2 उपयोग न करने का कारण

शहरी क्षेत्रों में करीबन 75% महिलाओं ने कहा कि वे मोबाइल पर इंटरनेट उपयोग में सक्षम नहीं हैं, जबकि 11% ने अपने हैंडसेट को इसके लिए सक्षम नहीं माना। शहरी बस्तियों की 20% महिलाओं ने इसके लिए अन्य कारण को जिम्मेदार माना। ग्रामीण क्षेत्रों की 94% महिलाओं ने कहा कि उन्हें मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग करना नहीं आता। इंटरनेट के उपयोग पर आने वाला खर्च 4% शहरी और 5% ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ी रुकावट रहा।

6.3 इंटरनेट का उपयोग कहाँ

भोपाल और इंदौर में शहरी बस्तियों के बाहर एक किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट कैफे/एमपी ऑनलाइन की सुविधा है। लेकिन गांवों में सबसे करीब के इंटरनेट कियोस्क या एमपी ऑनलाइन केंद्र के लिए औसतन 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण महिलाओं में 97% ने कहा कि उन्होंने कभी भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट का उपयोग नहीं किया है। शहरी बस्तियों में जो 6 महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं, उनमें से आधी अपने मोबाइल फोन पर और बाकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क का सहारा लेती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 91% महिलाओं को ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग के लिए जनपद पर एमपी ऑनलाइन या लोकसेवा केन्द्र तक जाना पड़ता है।

7. डिजिटल प्रसारण

टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट (TAM) के सालाना सर्वे (यूनिवर्सल अपडेट–2014)[10] के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में सात करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.8 करोड़ घरों में टीवी उपलब्ध हैं। शहरी क्षेत्रों में 36% घर अभी भी एनालॉग प्रसारण से जुड़े हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 36% है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 32% परिवारों[11] के पास टेलीविजन की सुविधा है। TAM के आंकड़े बताते हैं कि इनमें से 9 लाख परिवार[12] डीटीएच सुविधा से जुड़े हैं, जबकि 91 लाख परिवार डिजिटल केबल प्रसारण का लाभ ले रहे हैं। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में डिजिटल प्रसारण सेवाओं के दायरे से 47% डीटीएच परिवार बाहर हैं।

7.1 टेलीविजन वाले परिवार

भोपाल और इंदौर दोनों शहरों में प्रसारण सेवाओं का डिजिटलीकरण हो चुका है। फिलहाल दोनों शहरों में प्रसारण डिजिटल केबल या डीटीएच के जरिए हो रहा है। हालांकि एनालॉग प्रसारण अभी बंद नहीं हुआ है, इसलिए डिजिटल प्रसारण से नहीं जुड़े परिवार एनॉलॉग प्रसारण भी प्राप्त कर रहे हैं। शोध में शहरी क्षेत्र की 83% महिलाओं ने कहा कि

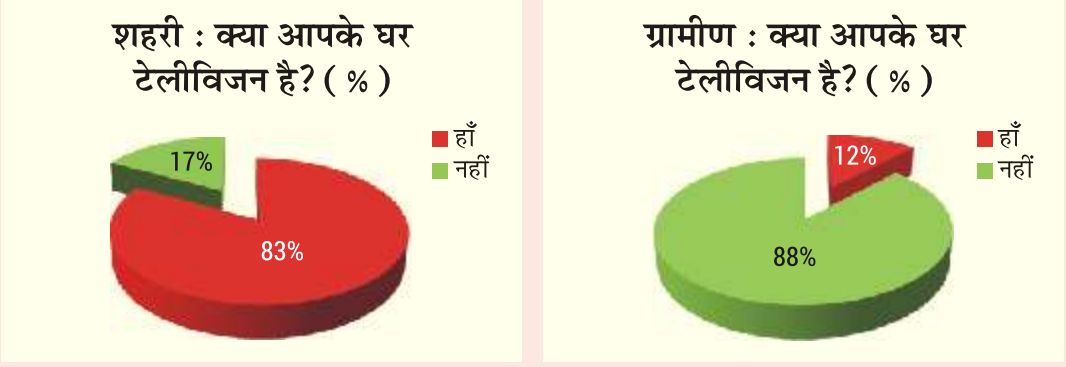

आंकड़े 43 : टीवी धारक परिवार

[10] http://www.tamindia.com/ref_pdf/Overview_Universe_Update-2014.pdf
[11] http://www.censusindia.gov.in/2011census/hlo/hlo_highlights.html
[12] आईएमआरबी और टैम समूह का अध्ययन और अनुमान : सितंबर 2014

उनके घर पर टीवी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 12% महिलाओं ने ही कहा कि उनके घरों में टेलीविजन उपलब्ध है। इसका एक प्रमुख कारण शोध क्षेत्र के कुछ गांवों में बिजली न होना और गांवों की बसाहट से जुड़ी भौगोलिक चुनौतियां हैं, जिनके कारण प्रसारण बाधित होता है।

7.2 टीवी देखने का पर्याप्त समय मिलता है

शहरी क्षेत्र की 83% महिलाओं ने कहा कि उन्हें घर पर टीवी देखने का पर्याप्त समय मिल जाता है। जिन महिलाओं को टीवी देखने का समय नहीं मिल पाता है, उन्होंने इसके पीछे कामकाजी दबाव को बड़ा कारण बताया। वहीं 62%ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि कामकाजी दबाव के कारण या फिर जब वे अपना पसंदीदा चैनल देखना चाहती हैं, तब टीवी पर परिवार के अन्य सदस्यों का कब्जा होता है। ऐसे में उनके पास टीवी देखने के लिए अनुकूल और पर्याप्त समय नहीं हो पाता।

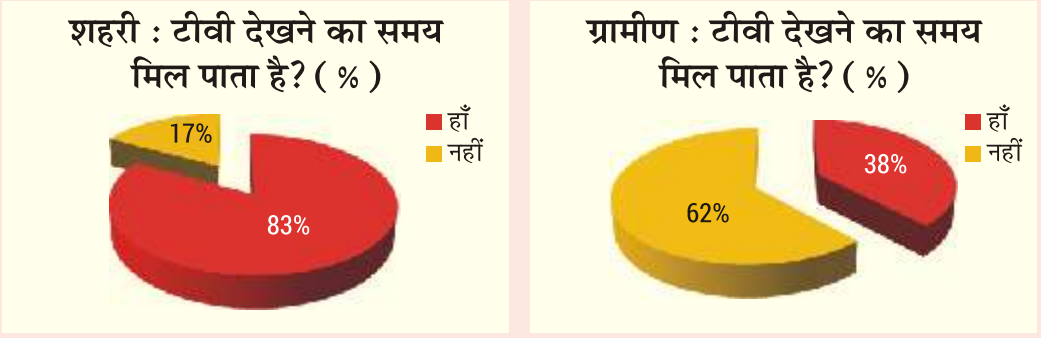

आंकड़े 44 : टेलीविजन देखने का कितना समय मिल पाता है

7.3 रिमोट का नियंत्रण किसके पास

शहरी क्षेत्र की करीब 32% महिलाओं ने कहा कि टेलीविजन पर क्या देखना है, इसका चुनाव परिवार के पुरुषों के

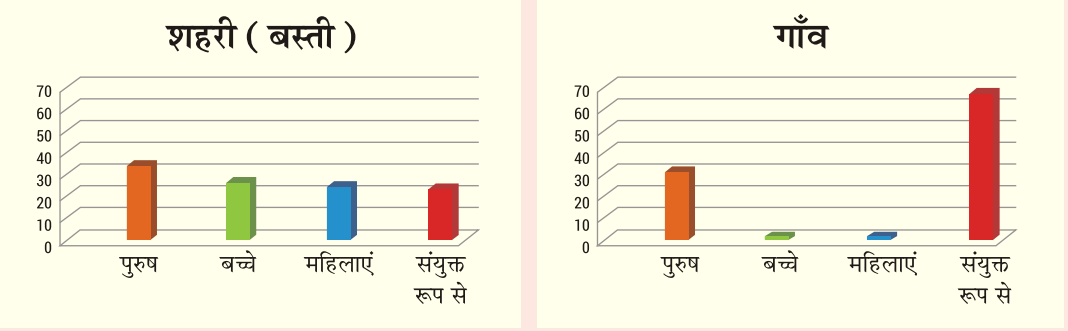

आंकड़े 45 : टीवी के रिमोट का नियंत्रण

पास है, जबकि 22% ने कहा कि चैनलों के चुनाव में उनकी राय ज्यादा मायने रखती है। 21% का कहना था कि इसका निर्धारण परिवार के सदस्य मिल जुलकर कर लेते हैं। दूसरी ओर 67% ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि टीवी पर चैनलों का चुनाव परिवार में सामूहिक रूप से किया जाता है। पुरुषों के आधिपत्य की बात 21% महिलाओं ने ही कही।

7.4 क्या आप टीवी चला पाती हैं

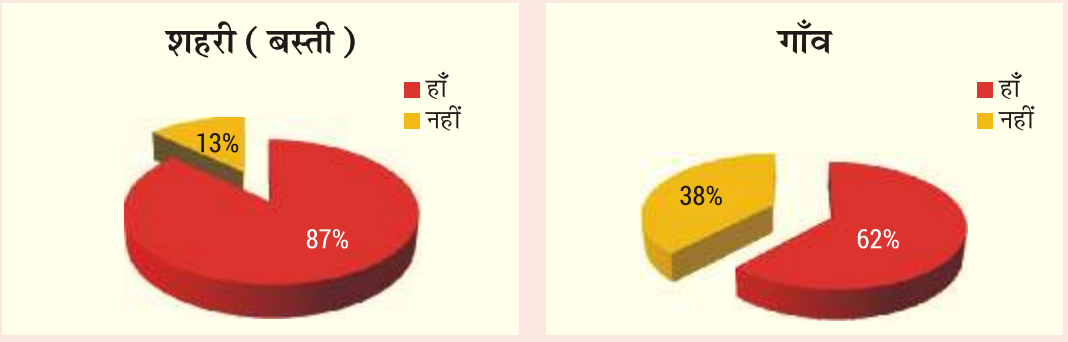

आंकड़े 46 : टीवी चला पाने की सक्षमता

डिजिटल प्रसारण सुविधा वाले सेट टॉप बॉक्स का रिमोट परंपरागत एनालॉग रिमोट से थोड़ा जटिल होता है। इसे चला पाना कम शिक्षित या अनपढ़ महिला के लिए चुनौती है। लेकिन 62% शहरी महिलाओं ने कहा कि वे खुद रिमोट के जरिए टीवी चला लेती हैं। हालांकि, 38% ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि उन्हें रिमोट के जरिए टीवी चलाने में परेशानी होती है।

8. निष्कर्ष

➢ वर्तमान दौर में तकनीक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। मोबाइल फोन ऐसी ही एक तकनीक है, जो न केवल शहरी इलाकों में, बल्कि अपनी सर्वसुलभ उपलब्धता के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है। सरलता से उपयोग में आने वाली यह तकनीक हाशिए पर खड़ी शहरी और ग्रामीण महिला को अधिकार संपन्न बनाने में बहुत ही फायदेमंद है। मोबाइल फोन के सहारे शहरी महिलाएं अपने करियर को संवारने के विकल्पों की तलाश कर सकती हैं, आजीविका के साधन ढूंढ़ सकती हैं और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अन्य उपयोगी सुविधाओं का लाभ ले सकती हैं। सबसे अहम बात यह है कि मोबाइल फोन हमें अभिव्यक्ति की शक्ति देता है। हम अपने विचार, सुझाव आपस में साझा कर सकते हैं। इससे हमारी निर्णयशक्ति भी मजबूत होती है। लेकिन हाशिए पर खड़े समुदाय की महिलाओं तक मोबाइल फोन की पहुँच में सबसे बड़ी रुकावट इस डिजिटल साधन की अपनी पसंद के अनुसार उपयोग करने की उनकी स्वतंत्रता न होना है। इसे देखते हुए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि मोबाइल फोन का स्वामित्व महिलाओं के हाथ में हो।

➢ मोबाइल फोन के स्वामित्व को लेकर हाशिए पर खड़े समुदाय में महिला और पुरुष के बीच का फासला मिटने के बाद मोबाइल तकनीक की उपयोगिता को स्वीकार्य बनाने में मदद मिल सकती है। यह कदम निजता के मुद्दे का भी समाधान करता है। ग्रामीण हिस्सों में मोबाइल फोन की पहुँच की दर को देखते हुए हमें आशा है कि इस डिजिटल साधन के स्वामित्व का फासला कम हो सकेगा। मोबाइल बैलेंस ऋण, कम से कम दो आपातकालीन फोन नंबरों पर मुफ्त फोन करने की सुविधा और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे विषयों पर स्थानीय भाषा में सामग्री उपलब्ध कराने की जरूरत भी है। इसी तरह निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को शहरी और ग्रामीण इलाकों में कार्यरत स्वसहायता समूहों को उपयोगकर्ताओं के समूह (सीयूजी) से जोड़ने की जरूरत है, जिससे उन्हें किफायती दरों पर मोबाइल सेवाएं मिल सकें।

➢ सर्वेक्षण में सामने आया है कि करीबन 50 प्रतिशत मोबाइल उपयोगकर्ता 15–35 साल के आयु समूह के हैं, ऐसे में टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को कॅरियर और रोजगार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षित ग्रामीण महिलाओं के पास रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों का रुख करने के मौके हैं, लेकिन वे परंपरागत साधनों से अवसरों की तलाश नहीं कर सकतीं। उन्हें मोबाइल फोन जैसा डिजिटल साधन चाहिए। अब जबकि ज्यादातर शहरी महिलाएं मोबाइल फोन और अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से रोजगार के अवसरों की तलाश कर रही हैं, जरूरत इस बात की है कि नौकरी के अवसरों, कॅरियर परामर्श, व्यक्तित्व विकास और प्रबंधकीय मसलों के बारे में सामग्री स्थानीय भाषा में तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराया जाए।

➢ शहरी वंचित समुदाय में इंटरनेट अब कोई अंजान तकनीक नहीं है। समुदाय में कई लोगों ने इंटरनेट के बारे में सुना है और लोगों को अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट का उपयोग करते देखा है। बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों को इंटरनेट तकनीक के उपयोग और इसके फायदों के बारे में कौन बताएगा कुछ निजी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों ने लोगों को स्मार्टफोन और मुफ्त इंटरनेट डाटा पैकेज देकर उन्हें जागरूक करने की पहल की है। लेकिन ऐसी पहल को स्कूल स्तर से लेकर विभिन्न महिला समूहों तक ले जाने की जरूरत है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर इंटरनेट सुविधा केन्द्र स्थापित करने पर जोर देना चाहिए, ताकि समुदाय को इंटरनेट तक पहुँच बनाने के लिए दूर न जाना पड़े।

•••

अध्याय 4

गुणात्मक विश्लेषण

मध्यप्रदेश में ब्रॉडबैंड और प्रसारण सेवाओं तक वंचित वर्ग की पहुँच को विस्तार से समझने के लिए आंकड़े जुटाते समय शोध के दौरान कुछ गुणवत्तामूलक प्रणालियों का भी उपयोग किया गया था। इस गुणवत्तामूलक अध्ययन में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल में असमानता के मुद्दे को दो रूपों में देखा गया। पहला तो यह कि लोग सूचना–प्रसारण की नई तकनीक के बारे में क्या सोचते हैं और दूसरा डिजिटल तकनीक को नियंत्रित करने वाली नीतियां, कानून और हमारे शोध क्षेत्र की जमीनी स्थिति इस बारे में क्या कहती हैं।

भाग–1 : डिजिटल तकनीक के बारे में लोगों की राय

मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल टीवी के रूप में सूचना संचार की आधुनिक तकनीक धीरे–धीरे दूर–दराज के गांवों और शहरों में वंचित वर्ग की रहवासी बस्तियों तक पहुँचने लगी है। इस तकनीक की पहुँच से लोगों को आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक रूप से अधिकार संपन्न बनाने में काफी मदद मिली है। डिजिटल तकनीक ने लोगों को वे बातें सिखाई हैं, जिनके बारे में वे पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्हें उनकी क्षमताओं से परिचित कराने और उनमें विश्वास पैदा करने का काम इस तकनीक ने बखूबी किया है। मध्यप्रदेश के दूरस्थ अंचलों में अलग–थलग पड़े गांवों तक पहुंचना भले ही बेहद मुश्किल हो, लेकिन उनके जीवन में डिजिटल तकनीक की छाप आसानी से देखी जा सकती है। कम से कम इस तकनीक तक लोगों की बुनियादी पहुँच ने उनके भौगोलिक और सामाजिक अलगाव को खत्म तो किया ही है। इससे वे भी वैश्विक गांव का हिस्सा बन उसे झकझोरने की कगार पर पहुँच चुके हैं। आधुनिक डिजिटल तकनीक ने सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के जीवन को रोशन करने में अहम भूमिका निभाई है, फिर भले ही उन्हें अपने घर में बिजली की आमद के लिए अभी तक इंतजार क्यों न करना पड़ रहा हो।

इस तरह, शोध क्षेत्र में डिजिटल तकनीक की पहुँच, उसके प्रति वंचित समुदाय की दिलचस्पी और यहां तक कि बहिष्कार से जुड़ी कहानियां भी दर्ज की गईं। इन कहानियों से पता चलता है कि शोध क्षेत्र के युवाओं की डिजिटल संचार साधनों और माध्यमों के बारे में जानकारी उनके जीवन और सामाजिक छवि को बेहतर बनाने का जरिया है। डिजिटल संचार साधन महिलाओं की भी आवाज बन रहा है। खासतौर पर मोबाइल फोन महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें शोषण से बचाने में महत्वपूर्ण साधन बन रहा है।

डिजिटल संचार साधनों के और भी कई फायदे हैं, जो धीरे–धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे, पास के इंटरनेट केयोस्क से कम्प्यूटर का एक बटन दबाकर रिजल्ट जाना जा सकता है। सरकार से आम नागरिकों को मिल रहीं सेवाओं के ऑनलाइन होने से सरकारी योजनाओं की हकदारी पाने में अब भ्रष्टाचार और शोषण का शिकार नहीं होना पड़ता। मोबाइल फोन का एक कॉल अगर जननी एक्सप्रेस सेवा या डॉक्टरी इलाज तक पहुँच मुमकिन कर सके तो एक जीवन को बचाया जा सकता है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं, अगर उनके मोबाइल पर सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुँच सके। आर्थिक रूप से कमजोर तबके की अगर मोबाइल फोन तक पहुँच बने तो रिश्तेदारों, दोस्तों से संपर्क साधने के लिए उन्हें लंबी यात्राएं न करनी पड़ें और उनका खर्च कम हो। इन सभी में मोबाइल फोन की उपयोगिता सबसे अहम है और यही कारण है कि दूरस्थ अंचलों में भी मोबाइल फोन अब केवल एक मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि संपर्क का सबसे आसान और लोकप्रिय माध्यम बन गया है। इन सबके बावजूद डिजिटल क्रांति को समाज के सबसे वंचित तबके तक पहुँचने में अभी लंबा सफर तय करना है। हमारे अध्ययन में इस तकनीक की पहुँच की जमीनी स्थिति का गुणात्मक आंकलन लोगों के इस बारे में नजरिए को समझते हुए किया गया है। इस गुणात्मक अध्ययन को तीन भागों में बांटा गया है– युवाओं, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों के नजरिए के रूप में।

1. युवा वर्ग का नजरिया

'कोई भी पर्याप्त रूप से उन्नत तकनीक किसी जादू से कम नहीं है' – आर्थर क्लार्क

शारीरिक रूप से निशक्त लेकिन अत्यंत जुझारू 22 वर्षीय पिंकी हर्वे इंदौर के राहुल गांधी नगर में रहती है। ग्रैजुएशन की पढ़ाई कर रही पिंकी का कहना है, 'डिजिटल तकनीक के विभिन्न माध्यमों के इस्तेमाल और इस मामले में पीछे रह जाने के बीच अंतर केवल इतना है कि इससे हमारी आय और जीवन स्तर में एक बड़ा फासला पैदा होता है।' डिजिटल तकनीक से युवाओं का जुड़ाव होने या न होने का सवाल उनकी सीखने की इच्छा पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे सभी इस तकनीक से खुश हैं। असल बात तो तमाम भौगोलिक चुनौतियों, परिवार की आर्थिक क्षमता और लैंगिक नजरिए के बीच इस तकनीक तक उनकी पहुँच पर आकर टिकती है। डिजिटल तकनीक तक पहुँच के मामले में लड़कियों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्हें मोबाइल फोन जैसी तकनीक के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाती। इसके पीछे धारणा यह है कि वे मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ज्यादा 'समझदार' हो जाएंगी या फिर उन्हें कोई बाहरी व्यक्ति बहला–फुसलाकर भगा ले जाएगा। लेकिन इससे बेपरवाह लड़कियां चाहे वे पितृसत्तात्मक परिवार या गरीब परिवार से ही क्यों न हों, चुपचाप डिजिटल माध्यमों के उपयोग को सीख रही हैं।

डिजिटल तकनीक तक पहुँच बनाने वाले लोगों की जिंदगी में सुधार भी नजर आए। जैसे एक फोटो स्टूडियो में सफाई का काम करने वाले युवक ने प्रायमरी तक की शिक्षा के बावजूद फोटो एडिटिंग सीखी। इसे सीखने के बाद युवक की आय बढ़ी। दूसरी ओर इस तकनीक तक पहुँच न बना पाने का खामियाजा मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के एक ग्रामीण को एक नहीं, बल्कि दो बार नौकरी के मौके गंवाकर भुगतना पड़ा। फिर भी शीशे के दूसरी ओर वंचित समुदायों के युवाओं को डिजिटल तकनीक ने बेहतर भविष्य की उम्मीद बंधाई है। यह तकनीक उनके लिए उस जादुई छड़ी के समान है, जो न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि उन्हें सूचित भी करती है।

2. महिलाओं का पक्ष

'समुद्री यात्रा की सार्थकता नए स्थानों की खोज में नहीं, बल्कि उन्हें नई दृष्टि से देखने में है' - चार्ल्स डिकेन्स

डिजिटल तकनीक से केवल संचार ही नहीं, मनोरंजन और सूचना प्राप्ति के रूप में भी फायदे मिलते हैं। मोबाइल या डिजिटल टेलीविजन पर आने वाला कोई गाना, धारावाहिक, समाचार यहां तक कि विज्ञापन भी प्रतिक्रिया के रूप में एक आवाज को मुखर करता है। यह जागरूक बनाता है, नई उम्मीदें पैदा करता है, जो समय के साथ जरूरत बनकर गूंजती है। चाहे युवा लड़कियां हों या प्रौढ़, विवाहित महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों या मजदूरी करने वाली अल्प शिक्षित या अशिक्षित महिला, डिजिटल तकनीक ने उन्हें खोजकर्ता बनाने के साथ ही उनकी दृष्टि को बदलने में भी अहम भूमिका निभाई है। धारावाहिक की किसी पात्र की नई साड़ी उन्हें उसी तरह का कोई उत्पाद ढूंढने को प्रेरित करती है। खबरें बताती हैं कि दुनियाभर में क्या हो रहा है। स्वच्छता के लिए डायपर्स जरूरी हैं और इन्हें नजदीक से ही खरीदा जा सकता है और यह संदेश टेलीविजन के एक विज्ञापन से मिल जाता है। इसी तरह महिला हिंसा के खिलाफ दिखाए जाने वाले संदेश न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि उनके परिवार और पड़ोसियों के लिए भी आवाज बनकर उभरते हैं।

डिजिटल संचार साधनों से महिलाओं को बाहर रखने की वजह अमूमन उस पितृसत्तात्मक मानसिकता में समाहित मिलती है, जहां समाज में सभी तरह की बेहतरी का अधिकार पहले पुरुषों का माना जाता है। पुरुषों को अगर कोई बात महिलाओं के लिए सुरक्षित लगती है तो ही वे उसकी अनुमति देते हैं। जगह, डिजिटल माध्यमों की उपलब्धता और कनेक्टिविटी, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर भी हालांकि महिलाओं के डिजिटल क्रांति का हिस्सा होने या न होने में योगदान देने वाला कारक है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है महिला का आत्मविश्वास और अपने आगे बढ़ने की उत्सुकता, जो उसे आखिरकार निर्णय के स्तर तक लेकर आती है।

इस अध्ययन के दौरान लक्षित समुदाय के बीच जाकर महिलाओं से चर्चा करने पर मालूम चला कि कई गरीब, अशिक्षित वंचित तबके की महिलाओं ने अपनी इच्छाशक्ति और जिज्ञासा के बलबूते पर डिजिटल तकनीक के विभिन्न माध्यमों, खासकर मोबाइल का संचालन (नंबर डायल करना, ब्लूटूथ का इस्तेमाल, डिजिटल टीवी के रिमोट को चलाना, इंटरनेट से सूचनाएं तलाशना आदि) सीख लिया। ये सब उन्होंने अपने आसपास के पुरुषों, जैसे पति, बेटे या पिता को देख कर सीखा।

3. वंचित वर्ग

'एक गरीब व्यक्ति अपने आप में अलग-थलग द्वीप की तरह होता है। सूचना तकनीक ऐसे व्यक्ति का अलगाव रातों-रात खत्म कर सकता है' - प्रो. मुहम्मद यूनुस

मध्यप्रदेश के कुछ सबसे पिछड़े जिलों, पन्ना, झाबुआ और डिंडोरी की यात्राओं और भोपाल, इंदौर की शहरी गरीब बस्तियों में भ्रमण के दौरान वंचित वर्ग से की गई चर्चाओं में मालूम चला कि डिजिटल संचार साधनों में से केवल एक, यानी मोबाइल फोन के जरिए दुनिया से जुड़ने का विचार ही इस तबके के लोगों को सशक्तिकरण का अहसास कराता है। यह डिंडोरी जिले के बैगा आदिवासी समुदाय को जंगलों की अवैध कटाई के खिलाफ शिकायत करने का

हौसला देता है। गांव की हिम्मती महिलाओं को मनरेगा की मजदूरी मिलने में हो रही देरी के खिलाफ सरपंच से सवाल–जवाब करने, विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने और एक फोन कॉल के सहारे किसी दूसरे व्यक्ति या अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय अपने अधिकारों की मांग करने की ताकत भी दे रहा है।

पन्ना जैसे जिले में, जहां काम की तलाश में लोगों का पलायन व्यापक समस्या है, ठेकेदार द्वारा गंतव्य स्थल पर पलायनकर्ताओं को बंधक बनाकर उनका शोषण करने के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। अब मोबाइल इस मामले में एक सुरक्षा कवच बनकर उभर रहा है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में पीड़ित पलायनकर्ता अपने मोबाइल फोन से गांव में अपने संबंधियों, करीबी लोगों से संपर्क साध सकते हैं। पलायनकर्ताओं को उनके मोबाइल नंबर के जरिए पंचायत में पंजीकरण करने के बाद उनकी निगरानी आसान हो जाती है। खासकर कार्यस्थल पर असुरक्षा, भेदभाव या शोषण के मामलों की जानकारी देने का एक आसान जरिया है मोबाइल फोन। पन्ना टाइगर रिजर्व के इर्द–गिर्द गांवों में हिंसक पशुओं के हमले की सूरत में एंबुलेंस बुलाने से लेकर नवजात और मातृ मृत्यु दर को कम करने में भी मोबाइल फोन की अहम भूमिका है। आर्थिक रूप से भी मोबाइल फोन की अहमियत लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर ठेकेदार से मजदूरी का काम मांगने और रोजगार के अन्य विकल्पों की तलाश में मोबाइल फोन मददगार है। इसके लिए गांव और शहर की भौगोलिक सीमाएं ज्यादा महत्व नहीं रखतीं। लोग चाहे भोपाल और इदौर में हों या फिर झाबुआ और डिंडोरी जैसे दूर–दराज के गांवों में, केवल काम की तलाश में अनिश्चितता को मोबाइल फोन ने खत्म किया है। मोबाइल फोन पर दो मिनट का एक कॉल दोस्तों, रिश्तेदारों से संपर्क के लिए लंबी यात्राओं के खर्च को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ है।

डिजिटल क्रांति, खासतौर पर मोबाइल स्मार्टफोन ने समाज में हाशिए पर खड़े लोगों को गीत–संगीत, वीडियो के रूप में मनोरंजन की एक खास सुविधा भी दी है, जो उन्हें अपने रहवास के नजदीक ही किसी छोटी सी दुकान में भी मिल जाती है। चाहे गांव में मोबाइल फोन का नेटवर्क हो या न हो, या फिर लोगों के पास मोबाइल को रिचार्ज करवाने के पैसे भले न हों, जेब में रखा मोबाइल फोन गाने और विडियो जैसे मनोरंजक साधनों की बदौलत ही जरूरत की वस्तु बन रही है।

डिजिटल संचार साधनों तक पहुंचने के संघर्ष में लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार कुछ खास प्रबंध भी किए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में जुगाड़ कहा जा सकता है। जैसे, अगर गांव में बिजली न हो तो कोई पांच रुपए देकर दो से तीन दिन तक के लिए अपने मोबाइल फोन की बैटरी किसी और स्थान से चार्ज करवा लेता है। यह भी देखने को मिला कि मोबाइल फोन की जरूरत पहले गाने और वीडियो से शुरू हुई और फिर दुनिया को जानने–समझने की चाहत व्यक्ति को स्मार्टफोन तक खींच लाई। आगे यही जरूरत व्यक्ति को कंप्यूटर या इंटरनेट आधारित सेवा देने वाले केंद्र तक पहुंचा देती है, जहां सरकारी नौकरियों, मंडी भाव, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लोक सेवाएं उपलब्ध होती हैं। धीरे–धीरे वंचित वर्ग यह समझने लगा है कि अगर गांव में किसी के पास भी उनकी जरूरत की सूचनाएं न हों, लेकिन सबसे नजदीकी इंटरनेट केयोस्क से उन्हें वांछित सूचनाएं मिल जाएंगी। पहले ऐसा सोचना भी उनके लिए असंभव था, लेकिन डिजिटल संचार साधनों की उपलब्धता ने उनकी उम्मीदों और अवसरों को पर लगाए हैं और इस बार उन्होंने तय किया है कि अशिक्षा, गरीबी और वंचितपन जैसी चुनौतियों क बावजूद वे दूसरों से पिछड़े नहीं बने रहेंगे।

भाग 2 : नीतिगत विश्लेषण

डिजिटल क्रांति के इस दौर में भारत वैश्विक रूप से तेजी से उभरता देश है। हमने तकनीक के क्षेत्र में काफी तरक्की की है, साथ ही जीवन के विभिन्न पक्षों में डिजिटल साधनों का उपयोग भी बढ़ रहा है। हम 1851 के टेलीग्राफ लाइनों के जमाने से आगे बढ़ते हुए 4 जी के जमाने में कदम रख चुके हैं। फिलहाल, देश के लाखों लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं, बल्कि मोबाइल फोन पर फिल्में देखने से लेकर जरा सी देर में फ्लाइट, ट्रेन और टैक्सी सेवाओं की बुकिंग भी कर लेते हैं।

इसी तरह देश में प्रसारण माध्यमों का विस्तार भी वैश्विक मानकों के अनुसार तो हुआ है, लेकिन पहुँच, प्रसारण सामग्री और तकनीक के लिहाज से यह अभी भी शहर केंद्रित है। सूचनाओं तक पहुंच और उसके फैलाव के मामले में इंटरनेट को जनसाधारण के बीच एक प्रभावी और कुशल माध्यम के रूप में स्थापित कर दिया है। ई–गवर्नेंस सेवाओं का देश के दूर–दराज तक विस्तार से भी इंटरनेट की लोकप्रियता बढ़ी है। हालांकि, इन सबके बावजूद सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग व्यापक स्तर पर शहरी संपन्न वर्ग के द्वारा किया जा रहा है, जबकि शहरी और ग्रामीण वंचित परिवारों की पहुँच से यह अभी भी दूर है।

ऐसे में दूरसंचार, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और डिजिटल ब्रॉडकास्ट तकनीकों के मामले में शहरों और गांवों के बीच पहुँच, इनके उपयोग की आर्थिक क्षमता और सहभागिता में एक बड़ा फासला साफ दिखाई देता है। इस असमानता के कई कारण नजर आते हैं। ढांचागत संसाधनों की उपलब्धता इसमें सबसे प्रमुख है। जैसे, कम्प्यूटर और सूचना तकनीक से जुड़े अन्य उपकरणों का खर्च, ग्रामीण समुदाय के लिए सामुदायिक संचालित केंद्रों की उपलब्धता बहुत कम होना, बिजली, शिक्षा, रोजगार के साधन और आय जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी अन्य कारणों में शामिल है। ये सभी कारण सरकार की पिछले वर्षों की नीतियों और उसके जमीनी प्रभाव से पैदा हुए हैं।

डिजिटल डिवाइड सिर्फ पहुंच का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सूचना–संचार साधनों के उपयोग में उन रुकावटों से जुड़ा है, जो सामाजिक–आर्थिक बेहतरी और अंतत: समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास पर असर करती हैं। जनसंख्या में हो रही बढ़ोतरी, अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, लोगों की क्रय क्षमता और सरकारी योजनाओं के अमल में विलंब वे चुनौतियां हैं, जिनके चलते समाज में असमानता व्याप्त है और डिजिटल डिवाइड के पीछे यही असमान विकास जिम्मेदार है। लैंगिक भेदभाव का मुद्दा इसमें बहुत प्रासंगिक है।

डिजिटल सूचना–संचार की जरूरत, सरकार की मंशा और इस तकनीक के वास्तविक जमीनी अमल को जानने–समझने के लिए यह जरूरी है कि इसके नीतिगत निर्णयों के पीछे के 'क्यों' और 'कैसे' को समझा जाए, ताकि सामाजिक विकास और सुशासन के लिए असमानता को खत्म किया जा सके।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994, 1999, 2004, 2012 के साथ राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नीति 2004, 2 जी, 3 जी स्पेक्ट्रम आवंटन और प्रबंधन, केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून 1995 में संशोधन, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम 2003 कानून, एफएम रेडियो के रूप में रेडियो फ्रिक्वेंसी के निजीकरण कानूनों का विश्लेषण, राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना और सीएससी व लोकसेवा केंद्रों के कामकाज और पन्ना जिले में ई–गवर्नेंस योजना के जमीनी अमल की मौके पर पड़ताल के साथ संचार और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से जुड़े लोगों, सेवा प्रदाताओं की राय जानने का प्रयास इसमें

किया गया।

इस शोध में प्रत्येक नीति के जमीनी परिणाम का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। जैसे केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून 1995 में 2011 को हुए संशोधन, जिसमें देशभर में टेलीविजन प्रसारण के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देशभर में लागू करने की बात कही गई है। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि उपभोक्ताओं को बेहतर क्वालिटी की प्रसारण सेवा तो मिल रही है, लेकिन कमजोर वर्ग के खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के वे परिवार जो सेट टॉप बॉक्स और डिजिटल एंटीना का खर्च नहीं उठा सकते, वे टेलीविजन प्रसारण के दायरे से बाहर हो रहे हैं।

ई–गवर्नेंस सेवाओं में कुछ नई बातों को जोड़ने पर एक शुरुआती अध्ययन करने की जरूरत है, ताकि नई प्रणाली और लोगों को उनकी आसान पहुँच में आ सकने वाली तकनीक से जोड़ा जा सके। लेकिन सामाजिक–आर्थिक–भौगोलिक सीमाओं को भेदकर देशभर में इसके सफल क्रियान्वयन का दावा निजी कंपनियों की बदौलत दी जा रहीं सेवाओं की गुणवत्ता किस हद तक निर्धारित कर पा रहा है, यह सवालों के घेरे में है। क्या सरकार की ई–गवर्नेंस सेवा समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को जोड़ पा रही है ?

देश में दूरसंचार क्षेत्र के पुनर्जीवन के लिए सरकार के स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधी फैसलों की अहम भूमिका है। यह इसलिए, क्योंकि सरकार के इन्हीं फैसलों का प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि मोबाइल सेवाएं किस तरह बेहतर उत्पादकता और उपयोगकर्ताओं के जीवन स्तर को सुधारने में सक्षम हों। अप्रासंगिक नीतियों का परिणाम सेवाओं में बेवजह की रुकावटों और असमानता के रूप में दिखाई पड़ता है। मोबाइल फोन का सामाजिक प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है और इसकी पहुँच बढ़ने से सरकार स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों से निपट सकती है। हालांकि, दूरसंचार क्षेत्र में पिछले कुछ समय में लिए गए सरकार के फैसलों ने मोबाइल फोन सेवाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना, कंपनियों को अधिग्रहण की अनुमति देना और स्पेक्ट्रम को साझा करने की अनुमति आदि। लेकिन अधिग्रहण करने वाली कंपनियों से स्पेक्ट्रम की ऊंची कीमत वसूलने, स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य को दुनिया के कुछ देशों की तर्ज पर अधिक रखने जैसे फैसलों ने, खासकर यह जानकर भी कि भारत में प्रति व्यक्ति औसत राजस्व कम मिलता है, दूरसंचार कंपनियों के उत्साह को कम किया है। ऐसे में सरकार ने बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप नीतियां बनाने, अनिश्चितता को खत्म करने और दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करने की नीति बनानी चाहिए, ताकि इस तकनीक का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके और आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी मुमकिन हो।

इससे भी ज्यादा अहम है कि सरकार केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि समुदायों की जरूरत को पूरा करने की मंशा से नीतियां बनाए। डिजिटल तकनीक के लिए नीति निर्धारकों को ग्रामीण समुदाय को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जिससे वंचित समुदाय को यह लगे कि यह तकनीक उनके लिए उपयोगी है, न कि संपन्न वर्ग के लिए। अब जबकि केंद्र की नई सरकार ई–गवर्नेंस को समाज के अंतिम छोर तक ले जाने को प्रतिबद्ध नजर आ रही है, उसे यह देखना चाहिए कि ऑनलाइन सेवाएं लोगों के घर के नजदीक तक कैसे पहुँचाई जाएं, ताकि उन्हें ये हमेशा उपलब्ध हो सकें।

•••

ISBN No. 978-93-81408-22-3